घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 299- मंगलवार 01- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

किर्गिस्तान में पुतिन-मोदी की मुलाकात, दोनों लीडर गले मिले: पीएम मोदी ने ब्रिक्स के लिए न्योता दिया

हमें युद्धों से हटकर आगे बढ़ना चाहिए : पीएम मोदी

बिश्केक,31 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को किर्गिस्तान के बिश्केक में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से मुलाकात की। इस दौरान दोनों लीडर एक-दूसरे के गले मिले। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान,मोदी ने पुतिन से कहा कि हमें कभी न खत्म होने वाले युद्धों से हटकर,उन्हें खत्म करने की ओर बढ़ना चाहिए। भारत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। पीएम ने पुतिन को सितंबर में होने वाले ब्रिक्स समिट में शामिल होने का न्योता दिया। इससे पहले मोदी ने ईरान,किर्गिस्तान और अर्मेनिया के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय मुलाकात की। मोदी ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजशकियान से भी मिले। बिश्केक में चल रही एससीओ समिट की थीम'शांति,विकास और समृद्धि के लिए मिलकर आगे बढ़ना' है।

मोदी ने पुतिन को ब्रिक्स समिट में शामिल होने का न्योता दिया...

पीएम मोदी ने भारत में अगले महीने होने वाली ब्रिक्स समिट के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन को न्योता दिया। मोदी ने कहा...'भारत कुछ दिनों बाद ब्रिक्स समिट का आयोजन कर रहा है। सभी सभी भारतीय आपका और आपके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। '

पुतिन बोले...रूस में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या 7 गुना बढ़ी

राष्ट्रपति पुतिन की बातों को ट्रांसलेट किया जा रहा है। ट्रांसलेटर ने कहा...'रूस में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या के मामले में भारत टॉप लिस्ट में शामिल है। पिछले कुछ सालों में यह संख्या 7 गुना बढ़कर 40,000 हो गई है। हम नियमित रूप से भारत और रूस के सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करते हैं। हमारे बीच पर्यटकों का आना-जाना भी काफी होता है,जिसमें 16% की वृद्धि देखी गई है। हम संयुक्त राष्ट्र,ब्रिक्स,जी20 और एससीओ में अपने प्रयासों में करीबी तालमेल रखते हैं। आज हमारे पास रूस-भारत संबंधों के विकास के बारे में विचारों का आदान-प्रदान करने और भविष्य के सहयोग की रूपरेखा तैयार करने का अच्छा मौका है। '

मोदी बोले...दोनों देश लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे : मोदी ने कहा...पिछले साल आपकी भारत यात्रा बहुत सफल और सचमुच यादगार रही। हमारे लिए यह बहुत संतोष की बात है कि हमारा सहयोग नई ऊंचाइयां छू रहा है और हम दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखना हमारा साझा दृष्टिकोण रहा है और भविष्य में भी यही हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत बना रहेगा।

मोदी ने कहा...हमें युद्धों को खत्म करने की ओर बढ़ना चाहिए

मोदी बोले...हमने हमेशा यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की है। पिछली बार जब हम मिले थे,तब भी आपने मुझे स्थिति के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। हमें कभी न खत्म होने वाले युद्धों से हटकर युद्धों को खत्म करने की ओर बढ़ना चाहिए। भारत शांति की दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। शांतिपूर्ण तरीकों से सभी मुद्दों का समाधान करना मानवता की पुकार है।

'पुतिन बोले... रूस और भारत के संबंध लगातार मजबूत हो रहे :

मीटिंग के दौरान पुतिन ने कहा...मैं खुशी के साथ यह कहना चाहूंगा कि रूस और भारत के संबंध एक खास और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी के सिद्धांतों के आधार पर लगातार मजबूत हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी,रूस-भारत संबंधों पर आपके विशेष ध्यान और हमारे बीच बने व्यापारिक और दोस्ताना रिश्तों से इसमें मदद मिली है। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। '

उज्बेकिस्तान में मोदी ने छात्रों से बात की...स्टूडेंट्स ने पीएम की कविताओं को हिंदी में सुनाया

पीएम मोदी बोले...भावनाएं बिल्कुल मेरे दिल जैसी थीं

ताशकंद,31 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान के दो दिवसीय दौरे में ताशकंद के महात्मा गांधी सेंटर का दौरा किया। यहां उज्बेक छात्रों ने हिंदी में मोदी की लिखी कविताएं सुनाई। अपनी कविताएं छात्रों से सुनकर मोदी भावुक हो गए। उन्होंने कहा... कि हिंदी छात्रों की मातृभाषा नहीं है,फिर भी उन्होंने कविताओं की भावनाओं को बिल्कुल वैसे ही समझकर पेश किया,जैसी भावनाएं उनके दिल में थीं। मोदी ने उज्बेकिस्तान में भारत,महात्मा गांधी और तमिल संस्कृति में बढ़ती रुचि का भी जिक्र किया। उन्होंने तिरुक्कुरल का उज्बेक भाषा में अनुवाद करने का सुझाव दिया। मोदी की यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के रिश्ते कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचे। दोनों देशों के बीच 11 समझौतों,एमओयू और सहमतियों का आदान-प्रदान भी हुआ। कार्यक्रम में भारत और भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने वाले एक उज्बेक इंडोलॉजिस्ट ने कहा कि शायद दुनिया में बहुत कम ऐसे देश होंगे,जहां लोगों में भारत को लेकर इतना प्यार है। उन्होंने बताया कि यहां लगभग हर नागरिक नमस्ते शब्द से परिचित है। भारतीय कला,नृत्य,संगीत,दर्शन और योग में भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। पीएम मोदी ने तमिल साहित्य की प्रसिद्ध रचना 'तिरुक्कुरल' का भी जिक्र किया। उन्होंने संस्थान की 80वीं वर्षगांठ का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि इसका उज्बेक भाषा में अनुवाद किया जाना चाहिए। मोदी ने कहा... कि तिरुक्कुरल के उज्बेक अनुवाद से वहां के लोगों को भारतीय दर्शन और विचारों को समझने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि प्राचीन भाषाओं में मौजूद दार्शनिक विचार बताते हैं कि सभ्यता के शुरुआती दौर से ही इंसान की सोच काफी गहरी रही है।

दिल्ली दंगों के 12 आरोपी हुए बरी

कोर्ट ने कहा...केवल भीड़ में शामिल होना दोष साबित नहीं करता...

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। दिल्ली की एडिशनल सेशंस कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा मामले में 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इन पर हत्या,दंगा भड़काने और डकैती के आरोप थे। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के खिलाफ सिर्फ इसलिए आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती, क्योंकि वह भीड़ का हिस्सा था। अदालत ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ निजी अपराध का सबूत जरूरी है। मामले की सुनवाई एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह कर रहे थे। मामले में लोकेश सोलंकी,पंकज शर्मा,अंकित चौधरी,प्रिंस,जतिन शर्मा,हिमांशु ठाकुर, विवेक पांचाल,ऋषभ चौधरी,सुमित चौधरी,टिंकू अरोड़ा,संदीप और साहिल आरोपी थे। कोर्ट ने कहा...'सिर्फ भीड़ के साथ दिखने से यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी घर में तोड़फोड़,लूट और आगजनी करने वाली भीड़ का हिस्सा बने रहे।अदालत ने मामले में पुलिस के गवाह का बयान भी खारिज कर दिया। सभी 12 आरोपी मुरसलीन की हत्या से जुड़े मामले में आरोपी थे। दरअसल,दंगों के बाद मुरसलीन नाम के व्यक्ति का शव 28 फरवरी 2020 को जौहरीपुर तिराहे के पास एक नाले में मिला था। मामले में मुख्य गवाह दिवेश राजपूत को मुरसलीन की हत्या का चश्मदीद बताया गया था। लेकिन सुनवाई के दौरान वह अपने बयान से मुकर गया।

दिल्ली में बस में 16 साल की छात्रा से गैंगरेप

ग्रेटर नोएडा से बैठाया,बस 47 किमी दौड़ती रही शीशे पर पर्दे लगे थे,ड्राइवर-कंडक्टर अरेस्ट

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। दिल्ली में 16 साल की छात्रा से चलती स्लीपर बस में गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना 4 अगस्त की है,पुलिस ने 31 अगस्त को इसकी जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक पीड़ित ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर बस में बैठी। आरोपियों ने उसे कश्मीरी गेट पर छोड़ा। इस दौरान बस करीब 47 किमी दौड़ती रही। बस के शीशों पर पर्दे लगे थे। पुलिस ने बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी कब हुई,इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। पीड़ित उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की रहने वाली है और 11वीं की छात्रा है। पुलिस के मुताबिक,पीड़ित यूपी के मैनपुरी की रहने वाली है। परिवार में झगड़ा होने पर बिना बताए नोएडा में कजिन के घर के लिए बस से निकली। मैनपुरी से नोएडा की दूरी 300 किमी से ज्यादा है। भारी बारिश और अंधेरे के कारण छात्रा गलती से परी चौक पर उतर गई थी। फिर यहां से नोएडा जाने के लिए वाहन का इंतजार करने लगी। इसी बीच वहां से एक खाली स्लीपर बस गुजरी। छात्रा ने बस को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर और कंडक्टर ने छात्रा को बस में बैठा लिया। उन्होंने बताया कि बस नोएडा सेक्टर-63 जा रही है। पुलिस के मुताबिक,बस चलने के कुछ समय बाद कंडक्टर ने छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। छात्रा ने पुलिस को बताया कि ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ रेप किया।

सोनिया गांधी की किताब नहीं छापेगा पेंगुइन इंडिया

कहा...फैसला किसी प्रेशर की वजह से नहीं लिया,राइटर्स की टीम से सहमति नहीं बनी

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंगः ए जर्नी ऑफ लव' प्रकाशित नहीं करने केके फैसले पर फिर सफाई दी है। पब्लिशर ने कहा कि इस फैसले के पीछे कोई बाहरी दबाव नहीं था,बल्कि पर चर्चा के दौरान एक खास मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। हालांकि पेंगुइन ने उस मुद्दे के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। पब्लिशर ने इसके लिए समझौते और लेखक की गोपनीयता का हवाला दिया है। यह सफाई कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के संस्मरण के भारत में प्रकाशन को लेकर चल रहे विवाद के बीच आई है। प्रकाशन इससे पहले भी सफाई दे चुका है। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की प्रवक्ता पल्लवी नारायण ने पीटीआई से कहा,किताब की सामग्री गोपनीय है और अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। इसलिए इस मामले में किसी भी तरह का बाहरी दबाव नहीं था। उन्होंने कहा,'पांडुलिपि सामान्य संपादकीय प्रक्रिया से गुजरी थी। इस दौरान कई मुद्दे उठाए गए और सोनिया गांधी के प्रतिनिधियों के साथ उन पर चर्चा की गई।'

प्रयागराज एयरफोर्स स्टेशन के पास पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट..

11 की मौत,इनमें 8 बच्चे,तड़पते घायलों को चारपाई पर लेकर भागे लोग

प्रयागराज,31 अगस्त 2026। यूपी में सोमवार को प्रयागराज और कौशांबी बॉर्डर पर एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 8 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत हो गई,जबकि 5 झुलस गए। पुलिस के मुताबिक,विस्फोट इतना भीषण था कि पूरी फैक्ट्री जमींदोज हो गई। 100 मीटर के दायरे में बने 8 मकान क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें से 3 ढह गए। हादसा दोपहर साढ़े 12 बजे कौशांबी जिले के मोहम्मदपुर गांव में हुआ। यह गांव प्रयागराज बॉर्डर पर है। यहां से मनौरी स्थित एयरफोर्स स्टेशन 2 किमी है। पुलिस,एयरफोर्स,एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 200 जवान रेस्क्यू में जुटे हैं। 10 बुलडोजरों से मलबा हटाया जा रहा है। पुलिस को शक है कि मलबे के नीचे कुछ लोग दबे हो सकते हैं। ऐसे में मौत का आंकड़ा और बढ़ सकता है। हादसे के वक्त फैक्ट्री में 7 मजदूर काम कर रहे थे। इनमें से 3 की जान गई है। बाकी 8 मरने वाले आस-पास के घरों के हैं। धमाका कैसे हुआ,पुलिस पता लगा रही है। हालांकि प्रयागराज में स्वरूप रानी अस्पताल पहुंची रानी ने बताया...बिजली का खंभा गिरने के बाद फैक्ट्री में रखे बारूद में तेज धमाका हुआ। धमाके की आवाज 2 किमी दूर तक सुनाई दी। कुछ ही देर में धुएं का गुबार चारों तरफ छा गया। ग्रामीण झुलसे लोगों को चारपाई पर ले जाते दिखे। विस्फोट की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मकान की तीसरी मंजिल में 8 फीट का छेद हो गया। एक मंजिला अवैध फैक्ट्री 600 वर्गफीट में बनी थी। मालिक का नाम आदिल है। पुलिस के मुताबिक, फैक्ट्री के बगल में नई बस्ती बस रही थी। आदिल,पिता नौशाद,चाचा शकील और तीन महिलाओं पर केस दर्ज किया है। गिरफ्तारी के लिए 4 टीमें बनी हैं।

कौशांबी में पटाखा फैक्ट्री संचालक समेत 6 पर एफआईआर,मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख मिलेंगे

कौशांबी पटाखा फैक्ट्री विस्फोट मामले में संचालक समेत 6 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। नामजद आरोपियों में संचालक के पिता नौशाद,चाचा शकील,मां,चाची और एक अन्य महिला शामिल हैं। मामले की जांच जारी है। सीएम योगी ने मुआवजे का ऐलान किया। उन्होंने कहा,मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार दिए जाएंगे।

डिप्टी सीएम केशव ने घायलों से मुलाकात की...

केशव मौर्य ने प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल पहुंचकर घायलों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एक ही परिवार के कई लोगों की मौत बेहद दुःखद और हृदयविदारक है। सरकार की पहली प्राथमिकता घायलों की जान बचाना है। उनके इलाज में किसी तरह की कमी नहीं होने दी जाएगी। मामले में डीएम और एसएसपी को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा,उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

लोगों ने संचालक की दुकान में तोड़फोड़ की...

घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। गुस्साए लोगों ने पटाखा फैक्ट्री संचालक आदिल की कस्बे में स्थित दुकान में तोड़फोड़ कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराया। घटना के बाद इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है।

भारत में टाटा बनाएगा टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली जैवलिन,अमेरिकी कंपनी से करार

भारत में मजबूत डिफेंस वर्कफोर्स बनेगी,देश में अमेरिकी नौकरियों के मौके मिलेंगे

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। भारत ने अमेरिका से टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली एफजीएम-148 जैवलिन खरीदने का समझौता किया है। भारत ने जैवलिन प्रणाली के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। अब टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और जैवलिन जॉइंट वेंचर (जेजेवी) ने भारत में इस प्रणाली के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। यह करार भारतीय रक्षा उद्योग को खास मौके देगा और इंडो-पैसिफिक के लिए क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करेगा। अमेरिकी राजदूतावास की प्रवक्ता डाना जिए ने 28 अगस्त को पुष्टि की थी कि भारत ने जैवलिन प्रणाली के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ भारत जैवलिन प्रणाली का ग्राहक बन गया है,जो एक उन्नत,मध्यम दूरी की फायर-एंड-फॉरगेट एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल है। अब भारत में जैवलिन प्रणाली के निर्माण के लिए जैवलिन

जॉइंट वेंचर ने टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स को प्राइम पार्टनर के तौर पर चुना है। इस करार के तहत टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और जेजेवी भारत में जैवलिन प्रणाली के लिए एक फाइनल असेंबली और एकीकरण सुविधा बनाने के बारे में पता लगाएंगे। टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली एफजीएम-148 जैवलिन भारत और अमेरिकी पार्टनरशिप के लिए फायदेमंद होगी। इससे भारत में एक मजबूत डिफेंस वर्कफोर्स बनेगी। साथ ही कई साल के प्रोडक्शन के जरिए घरेलू सप्लाई चेन में अमेरिकी नौकरियां बनी रहेंगी। देश में को-प्रोडक्शन शुरू होने से भारत का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस मजबूत होगा। इससे जैवलिन की फाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन भारतीय फैसिलिटी और सप्लायर तक पहुंचेगा, हाई-टेक नौकरियां पैदा होंगी,स्थानीय विनिर्माण विशेषज्ञता बढ़ेगी और दुनिया भर में बढ़ती डिमांड के कारण ग्लोबल सप्लाई चेन की मजबूती को सपोर्ट मिलेगा। भरोसेमंद जैवलिन वेपन सिस्टम की सप्लाई होने से इस इलाके के पार्टनर देशों को मदद मिलेगी। जैवलिन जॉइंट वेंचर के वाइस प्रेसिडेंट और प्रोग्राम डायरेक्टर रिच लिसियन ने कहा कि यह साझेदारी जैवलिन जॉइंट वेंचर और भारतीय पार्टनर के बीच गहरे सामरिक सहयोग को दिखाती है,जिससे अंतरसंचालनीयता और संयुक्त रक्षा पहल को मजबूती मिलेगी,जो इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप के बड़े लक्ष्यों के साथ मेल खाती हैं।

केंद्र सरकार ने 1.27 लाख करोड़ रुपये की सेमीकॉन 2.0 योजना किया अधिसूचित

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। केंद्र सरकार ने देश में चिप विनिर्माण के पूरे तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय वाली सेमीकॉन 2.0 योजना को अधिसूचित किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जुलाई 2026 में इस योजना को अपनी मंजूरी दी थी। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सोमवार को सेमिकॉन 2.0 स्कीम से संबंधित आधिकारिक गजट अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के अनुसार योजना का उद्देश्य डिजाइन से लेकर मशीन,कच्चा माल, फैब्रिकेशन,टेस्टिंग और रिसर्च तक पूरी सप्लाई चेन तैयार करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में सेमीकॉन 2.0 के सभी छह स्तंभों पर बोलते हुए कहा,वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग के हितधारकों में यह दृढ़ विश्वास है कि आने वाले दशकों में बड़े निवेश के लिए भारत सही जगह है। उन्होंने आगे बताया कि सेमीकॉन 1.0 के तहत स्वीकृत इकाइयों की संख्या और अनुमोदन से लेकर शिलान्यास और फिर वाणिज्यिक उत्पादन तक की गति से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। एक मामले में, शिलान्यास के 13 महीनों के भीतर ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो गया। वैष्णव ने कहा कि कई मामलों में,सभी स्वीकृतियां पहले 200 दिनों या 150 दिनों के भीतर ही दे दी गईं, और एक मामले में तो 90 दिनों के भीतर ही। इस गति ने वैश्विक उद्योग को बहुत भरोसा दिलाया है।

सिंधु जल संधि विवाद : भारत ने खारिज किया मध्यस्थता अदालत का फैसला

कहा...संप्रभु फैसलों पर अधिकार नहीं

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। भारत ने सोमवार को विश्व बैंक द्वारा गठित सिंधु जल संधि से जुड़ी मध्यस्थता अदालत के फैसले को खारिज करते हुए उसे अवैध रूप से गठित निकाय बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस अदालत का भारत के संप्रभु फैसलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला लागू रहेगा। वहीं,मध्यस्थता अदालत ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित करने के लिए भारत द्वारा दिए गए आधार पर्याप्त नहीं हैं और संधि अभी भी पूरी तरह लागू है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि विश्व बैंक ने संधि की शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए इस तथाकथित मध्यस्थता अदालत का गठन किया है। भारत इस तथाकथित अदालत के फैसले को उसी तरह खारिज करता है, जिस तरह उसने पहले भी इस 'अवैध रूप से गठित' संस्था की सभी टिप्पणियों और फैसलों को खारिज किया है।

दिल्ली में 47 लाख नाम एसआईआर ड्राफ्ट रोल से बाहर

महाराष्ट्र के 2 करोड़ 7 लाख नाम छूटे,30 सितंबर तक आपत्ति दर्ज कराने की तारीख

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। महाराष्ट्र और दिल्ली में एसआईआर के तहत 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर रोल यानी प्रारूप मतदाता सूची जारी की गई। दिल्ली में कुल 1 करोड़ 45 लाख मतदाता हैं। इनमें से 47 लाख 56 हजार 722 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हैं। वहीं,महाराष्ट्र में करीब 2 करोड़ 7 लाख मतदाताओं के नाम फिलहाल ड्राफ्ट रोल में नहीं हैं। डिजिटाइजेशन के लिए फॉर्म जमा न होने और अन्य तकनीकी कारणों से कई मतदाताओं के नाम फिलहाल इस सूची में शामिल नहीं हो पाए हैं। इनमें अनुपस्थित,स्थानांतरित,मृत, डुप्लिकेट,विदेशी और अन्य मामले शामिल हैं। जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं हैं,वे 30 सितंबर 2026 तक दावा या आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। दावों और आपत्तियों का डिस्पोजल प्रोसेस 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके बाद 4 नवंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची जारी होगी।

दिल्ली, महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों में एसआईआर का तीसरा फेज : चुनाव आयोग ने 14 मई को हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र समेत 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (एसआईआर) की घोषणा की थी। यह एसआईआर का तीसरा फेज है। पूरी प्रक्रिया 30 मई से 23 दिसंबर तक चलेगी। इस दौरान 36.73 करोड़ वोटरों का वेरिफिकेशन हो रहा है। जिन राज्यों में एसआईआर होगा,उनमें पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। अन्य 13 राज्यों में 2028 और 2029 में चुनाव होंगे।

10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा हुआ एसआईआर : एसआईआर के पहले और दूसरे फेज में 10 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश कवर हो चुके हैं। एसआईआर के बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती है। केरल में कांग्रेस गठबंधन और तमिलनाडु में टीवीके ने जीत हासिल की है। असम में स्पेशल रिवीजन हुआ। यहां भी भाजपा सरकार की वापसी हुई।

संपादकीय

सीख लेनी होगी नेपाल की बाढ़ से

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) राज्यों के साथ मिल कर हिमालय की ग्लेशियर झीलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा रहा है। इसमें से उत्तराखंड रीजन में हम लोगों ने भी कुछ प्रोजेक्ट जमा किए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है एशियाई देशों में कहीं भी ग्लेशियर टूटने को लेकर बहुत प्रभावी अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है।

उसकी सटीकता भी ज्यादा नहीं है। यह मुश्किल काम भी है। आप सुनामी का अनुमान लगा सकते हैं कि भूकंप आया है तो सुनामी आएगी। दूसरी बात हिमालय बहुत दुरूह क्षेत्र हैं। यहां सभी जगह पहुंचना संभव नहीं है। हिमालय के अंदर 10,000 ग्लेशियर हैं। हिमालय अपने आप में खुद एक बहुत जटिल सिस्टम है,जिसे समझना बहुत मुश्किल है।

अब सवाल यह है कि हम अर्ली वार्निंग सिस्टम कहां लगाएं। बहुत अच्छा उदाहरण उत्तराखंड में दिखता है कि केदारनाथ में बाढ़ आई। आपने केदारनाथ घाटी और आसपास के क्षेत्र में फोकस किया तो अचानक ऋषिगंगा में बाढ़ आ गई वो भी जाड़े के मौसम में। यह अप्रत्याशित था। इसके बाद धराली में घटना हो गई। इसके बाद तमक में। अर्ली वार्निंग सिस्टम तब कारगर होता है जब आपको पता हो कि यहीं पर आएगा तो यहीं पर फिट कर दो।

यह भी सवाल है कि घाटी में लगाना कहां है क्योंकि एक घाटों में हजारों छोटे छोटे चैनल हैं जो सक्रिय हैं। आपको पता ही नहीं कि कहां टूटना है तो आप कैसे करोगे। सवाल यह नहीं है कि हमारा निगरानी तंत्र कितना कारगर है। सवाल यह है कि हम लोगों को जागरूक कैसे करें। लोगों को यह बताना होगा कि पर्वतीय क्षेत्र में आप कहां घर बनाएं। कहां इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करें।

नेपाल की बाढ़ यह सीख देती है कि आपको बस्तियां कहां बसानी है। आप नदी के किनारे ही कई मंजिल के घर बना रहे हैं। आपको हमेशा नदी के डूब क्षेत्र के बाहर घर बनाना चाहिए। यहां तक केदारनाथ त्रासदी ने भी सबक दिया था कि आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर कहां बनाना है। आपको यह याद रखना होगा कि आज नहीं तो कल बाढ़ का क्षेत्र अपनी पूरी जगह लेगा। अगर आप पहले के लोगों को देखें तो वे लोग हमेशा पहाड़ पर बहुत ऊंची जगह पर घर बनाते थे। नीचे नहीं बनाते थे। वे नदी के किनारे नहीं बैठे थे। अब नई सभ्यता में होम स्टे और तमाम चीजों के साथ बनी हैं और ये कहीं भी निर्माण कर रहे हैं। किसी भी राज्य की कोई आपदा नीति नहीं है कि इसमें तय किया गया हो कि आपको कहां घर बनाना है और कहां नहीं। तो लोग इसकी कीमत चुका रहे हैं और अगर सबक नहीं सीखा गया तो लोग आगे भी कीमत चुकाते रहेंगे।

किसी की प्यास ने बदल दी एक आईएएस अधिकारी की मंजिल

पद से पहचान मिली,लोगों से मिला...जीवन का अर्थ पदनाम के बाद बचा सिर्फ एक सवाल...अब किसके लिए?

त्यागपत्र आमतौर पर सेवा का अंत माना जाता है,लेकिन हर विदाई अंत नहीं होती। कुछ विदाइयां यह सवाल छोड़ जाती हैं कि असली सेवा आखिर होती

प्रो.आरकेजैन
बड़वानी,मध्यप्रदेश

क्या है...कुर्सी पर बैठकर निर्णय लेना या उस कुर्सी से बाहर निकलकर उन लोगों के बीच जाना, जिनके सपनों के नाम पर व्यवस्था खड़ी की गई है। उत्तर प्रदेश कैडर की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का लगभग 13 साल की सेवा के बाद इस्तीफा इसी सवाल को सामने रखता है। उनका कहना...'अब जनता के सपनों को जीने का समय आ गया है'...सिर्फ नौकरी छोड़ने की घोषणा नहीं,बल्कि उस यात्रा का अगला पड़ाव है जिसमें पद साधन था और मनुष्य मंजिल।

दिव्या मित्तल की कहानी में चमक भी है और बेचैनी भी। आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बैंगलोर से पढ़ाई,फिर लंदन में जेपी मॉर्गन जैसी प्रतिष्ठित संस्था की नौकरी–दुनिया की नजर में इससे बेहतर उपलब्धि क्या होती? मगर जीवन की कठिन कमी कभी-कभी उपलब्धियों से पूरी नहीं होती। विदेश में रहते हुए उन्हें अपने देश से दूर होने की टीस महसूस हुई। उन्होंने माना कि उनकी शिक्षा, आत्मविश्वास और दुनिया में कहीं भी सिर उठाकर चलने की क्षमता इसी मिट्टी का ऋण है। उसी ऋण ने उन्हें लौटाया। दो बार यूपीएससी दी;पहली बार (2012) आईपीएस चयन और दूसरी बार (2013) अखिल भारतीय रैंक 68 के साथ आईएएस। यह केवल परीक्षा की सफलता नहीं थी,बल्कि भीतर उठती पुकार का जवाब था।

मिर्जापुर ने उस पुकार को अर्थ दिया। लहुरियादह (मिर्जापुर के हलिया ब्लॉक का पहाड़ी गांव) में जब पाइप के रास्ते पानी पहुंचा और करीब सत्तर-पचहत्तर साल बाद पहली बार किसी नल से पानी निकला,तब विकास किसी सरकारी रिपोर्ट का शब्द नहीं रहा। वह पानी बनकर सामने था। एक वृद्ध महिला ने कोई भाषण या औपचारिक धन्यवाद नहीं दिया;उन्होंने बस कांपते हाथों से दिव्या के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। उस स्पर्श ने शायद किसी प्रशस्ति-पत्र से अधिक गहरी बात कह दी। दिव्या ने लिखा कि वह यह सोचकर आई थीं कि कुछ देने जा रही हैं,जबकि असल में सबसे ज्यादा उन्होंने ही पाया। यही वह क्षण है जब अधिकारी की आंख से फाइल हटती है और सामने इंसान दिखाई देता है। उनके अनुभवों की दूसरी किताब देवरिया और मिर्जापुर ने मिलकर लिखी। देवरिया ने उन्हें बताया कि सही के साथ खड़ा

होना सुविधा नहीं,कर्तव्य है। मिर्जापुर ने सिखाया कि 'असंभव' हमेशा पत्थर पर लिखी हुई सच्चाई नहीं होता,कई बार वह केवल किसी की बनाई हुई धारणा होता है। जमीन का अधिकार पाकर परिवार की आंखों में लौटती चमक,विकलांग व्यक्ति को मिलती गरिमा या किसान के खेत तक पहुंचता पानी–इन छोटे दिखने वाले बदलावों ने प्रशासन की बड़ी-बड़ी परिभाषाओं को उनके सामने छोटा कर दिया। तब सवाल उठना स्वाभाविक है कि जिसने व्यवस्था के भीतर रहकर इतने अर्थ खोज लिए,वह उसी व्यवस्था से बाहर क्यों चला गया?

इस प्रश्न का आसान उत्तर शायद कोई नहीं है। न उन्होंने किसी एक घटना को इस्तीफे का कारण बताया,न किसी टकराव को। उनका कहना है...'कुछ भी ट्रिगर नहीं हुआ। पिछले कुछ महीनों से लग रहा था कि मैं इस काम से हो गई हूं।' इस वाक्य को शिकायत की तरह पढ़ना भूल होगी। यह उस व्यक्ति की स्वीकारोक्ति है जिसने अपने हिस्से का रास्ता चलकर महसूस किया कि अब दिशा बदलनी चाहिए। व्यवस्था में रहकर परिवर्तन करना एक रास्ता है, लेकिन हर परिवर्तन का पता सरकारी पदनाम से होकर नहीं गुजरता। कभी-कभी पद से बाहर निकलना भी अपने विश्वास के प्रति ईमानदारी होता है।

यही कारण है कि उनका इस्तीफा उन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है,जो सिविल सेवा को अंतिम मंजिल मानकर वर्षों तक किताबों,परीक्षाओं और रैंक के बीच अपना भविष्य खोजते हैं। दिव्या का जीवन बताता है कि आईएएस बनना उपलब्धि हो सकती है,उद्देश्य नहीं। लंदन की सुरक्षित और प्रतिष्ठित नौकरी छोड़कर भारत लौटना एक चुनाव था;आईएएस की प्रतिष्ठित कुर्सी छोड़ना दूसरा। दोनों फैसलों के पीछे एक ही बेचैनी थी...अपने देश और लोगों के लिए कुछ करने की। अब उनके इस्तीफे के बाद राजनीति में जाने की अटकलें हैं। उनका जवाब है...'जब समय आएगा,तब बोलूंगी।'शायद यह मौन जल्दबाजी से बेहतर है,क्योंकि हर सपना घोषणा से नहीं,तैयारी से आकार लेता है।

दिव्या का जाना प्रशासनिक व्यवस्था के सामने एक असहज आईना रखता है। सिविल सेवा राज्य की रीढ़ है और स्वेच्छा से अलग होने वाला हर अधिकारी एक सवाल छोड़ता है...क्या व्यवस्था उन लोगों के लिए पर्याप्त जगह बना पा रही है, जिनकी बेचैनी केवल फाइल निपटाने से शांत नहीं होती? इसका अर्थ यह नहीं कि हर इस्तीफा व्यवस्था की विफलता है। लेकिन ऐसे फैसले हमें व्यवस्था के उद्देश्य पर फिर सोचने को मजबूर करते हैं। पद रहते हुए दिव्या ने पानी पहुंचाया; अब पद से बाहर निकलकर भी वे शायद उन प्यासों तक पहुंचना चाहती हैं,जिन्हें सरकारी सीमाएं नहीं छू पातीं। सेवा का रास्ता बदल सकता है, सेवा की प्यास नहीं।

आखिर में बचता है वही कांपता हाथ, जो एक बुजुर्ग महिला ने उनके सिर पर रखा था। सरकारी कुर्सी बदलती है, पदनाम मिट जाता है,फाइलें दूसरी मेज पर चली जाती हैं;लेकिन किसी की आंख में लौटी उम्मीद और किसी आंगन में पहली बार बहा पानी स्मृति से नहीं जाता। दिव्या मित्तल का इस्तीफा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं कि एक आईएएस अधिकारी ने नौकरी छोड़ दी। महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने पद और उद्देश्य में फर्क करने का साहस दिखाया। कुर्सी सेवा का माध्यम थी;जनता का सपना मंजिल। अब देखना है कि पद से मुक्त हुई यह ऊर्जा किस दिशा में बहती है। कुछ सपने कुर्सी पर बैठकर पूरे होते हैं,कुछ कुर्सी छोड़ने के बाद चलना शुरू करते हैं।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

चुनावों के समय ही अनुसूचित जाति जनजातियों वर्गों के साथ छलावा क्यों?

चुनावों के समय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों के साथ होने वाले छलावे या राजनीतिक लोकलुभावनवाद के पीछे मुख्य रूप से वोट बैंक की राजनीति,सामाजिक-आर्थिक निर्भरता और चुनावी रणनीतियाँ ज़िम्मेदार हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह एक जटिल मुद्दा है,जिसे निम्नलिखित प्रमुख कारणों से समझा जा सकता है :-

1. बड़ा और निर्णायक वोट बैंक चुनावी गणित: भारत की जनसंख्या में एससी और एसटी वर्ग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर इस वर्ग के मतदाता हार-जीत तय करने में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। समय-बद्ध सक्रियता : राजनीतिक दल पूरे पाँच साल इनके मुद्दों पर मौन रह सकते हैं, लेकिन चुनाव आते ही सत्ता पाने या बचाने के लिए इस बड़े समूह को लुभाना उनकी मजबूरी बन जाता है।

2. नीतिगत वादों और ज़मीनी हकीकत में अंतर घोषणा-पत्रों की राजनीति : चुनावों के दौरान राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं,विशेष भत्तों, नौकरियों और विकास पैकेजों की झड़ी लगा देते हैं। क्रियान्वयन का अभाव : चुनाव जीतने के बाद इन वादों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। बजट का सही आवंटन न होना और प्रशासनिक ढीलापन इन वर्गों तक वास्तविक लाभ नहीं पहुँचने देता,जिससे इन्हें छलावे का अहसास होता है।

3. सामाजिक और आर्थिक निर्भरता कमज़ोर आर्थिक स्थिति : इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा आज भी गरीबी,भूमिहीनता और बुनियादी सुविधाओं (शिक्षा, स्वास्थ्य) के अभाव से जूझ रहा है।तात्कालिक लाभ का जाल : आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण ये वर्ग चुनावों के समय मिलने वाले तात्कालिक लाभों (जैसे मुफ्त राशन,नकद ट्रांसफर या अन्य उपहारों) के प्रति संवेदनशील होते हैं,जिसका राजनीतिक दल फायदा उठाते हैं।

4. केवल प्रतीकात्मक राजनीति चेहरों का इस्तेमाल : चुनाव आते ही राजनीतिक दल इस वर्ग के नेताओं को मंच पर आगे करते हैं, उनके घरों पर भोजन करने के कार्यक्रम आयोजित करते हैं या प्रतीकात्मक सम्मान देते हैं।वास्तविक सशक्तिकरण की कमी: इस प्रतीकात्मक सम्मान के पीछे वास्तविक मंशा नीतिगत सुधार या इस वर्ग को नीति-निर्माण के मुख्य पदों पर बैठाने की नहीं होती,बल्कि केवल उनके समुदाय का वोट हासिल करने की होती है।

5. जागरूकता और संगठित आवाज़ की कमी शिक्षा का स्तर : हालांकि शिक्षा और जागरूकता बढ़ रही है,लेकिन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों (विशेषकर जनजातीय इलाकों) में आज भी राजनीतिक अधिकारों और सरकारी नीतियों के प्रति पूर्ण जागरूकता का अभाव है।विभाजन की राजनीति- राजनीतिक दल अक्सर इस वर्ग को भी उप-जातियों में बांटकर आंतरिक रूप से कमजोर कर देते हैं, जिससे ये अपनी मांगों के लिए एक मजबूत और संगठित दबाव समूह नहीं बन पाते।

सुधार का मार्ग : इस स्थिति को बदलने के लिए सतत राजनीतिक चेतना,गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता सबसे ज़रूरी हैं। जब यह वर्ग तात्कालिक चुनावी वादों के बजाय दीर्घकालिक विकास, रोज़गार, और आत्मसम्मान को अपनी मुख्य मांग बनाएगा,तब राजनीतिक दलों के लिए केवल चुनावों के समय छलावा करना असंभव हो जाएगा।

राजेन्द्र लहरे पामगढ़ छत्तीसगढ़.

आखिर टेट परीक्षा का फाटक टूट गया

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार शिक्षकीय सेवा में बने रहने के लिए बेसिक शिक्षा में कार्यरत सभी शिक्षक-शिक्षिकाओं को दो वर्ष में टेट

प्रमोद दीक्षित मलय
बांदा,उत्तरप्रदेश

अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य था। हालांकि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति का समय पांच वर्ष बचा था,उनको परीक्षा से छूट प्रदान की गई थी। फिर भी,शिक्षक-शिक्षिकाओं की एक बड़ी संख्या इस दायरे में आ रही थी। वर्ष 2011 से पूर्व भर्ती हुए शिक्षक-शिक्षिकाओं के सपनों पर तो मानो तुषारापात हो गया। शिक्षक संगठनों के आह्वान पर शिक्षक लामबंद हुए। जिला मुख्यालय से राज्यों की राजधानियों और दिल्ली तक धरना-प्रदर्शन कर विरोध आरम्भ हुआ, पर सरकार टस से मस नहीं हुई। किंतु टेट परीक्षा उत्तीर्ण करने का वर्ष एक वर्ष बढ़ाकर 2028 जरूर कर दिया गया।

शिक्षकों के सामने चुनौतियां मुंह बाये खड़ी थीं। शिक्षक-शिक्षिकाएं बातचीत में तमाम समस्याएं बताते। घर-परिवार का दैनंदिन खर्च,बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और वृद्ध बीमार माता-पिता की दवाई। एकमात्र कमाई का जरिया यह नौकरी ही है। और यदि नौकरी नहीं रही तो सभी व्यवस्थाएं चरमरा कर ढह जाएंगी। स्वाभाविक रूप से शिक्षक-शिक्षिकाओं के मन-मस्तिष्क में चिंता की रेखाएं उभर रही थीं और दबाव हावी था। वे कहते कि जीवन के इस पड़ाव में टेट परीक्षा किसी अभेद्य किले पर फतह करने जैसा है, जिसके मुख्य द्वार पर विशाल मजबूत फाटक लगा है। किंतु समस्या से जूझना ही था,टेट का फाटक तोड़ना ही था।शिक्षक-शिक्षिकाओं में कुछ ने अपने नगर के कोचिंग संस्थानों की शरण ली तो कुछ ने आनलाइन राह पकड़ी। घर में पिता और पुत्र-पुत्रियां साथ पढ़ने लगे। विद्यालयों में भी बचे समय का सदुपयोग गपशप की बजाय नोट्स बनाने में लगने लगा। जल्दी ही यूपी टेट परीक्षा का विज्ञापन निकला। धड़ाधड़ आवेदन किये जाने लगे। मुझ पर टेट परीक्षा का तो कोई खास दबाव-भय न था। अपनी पढ़ने-लिखने की रोजमर्रा की आदत और नियमित कक्षा शिक्षण के कारण विषय पर समझ और कमोबेश कुछ पकड़ थी ही। पर परीक्षा तो परीक्षा ही होती है,तो देह में सिहरन सी दौड़ जाती। मैंने भी फार्म भर दिया और विषयवार गाईड खरीद लीं। किंतु वे गाईड पुस्तकों की दूकान से जिस प्लास्टिक पन्नी में बंधकर आई थीं,उसी में अभी तक ज्यों की त्यों रखी हैं। खोलने-पढ़ने का समय ही नहीं मिल सका और वह पैकेट मेरी अन्य पुस्तक-पत्रिकाओं के ढेर में कहीं दबकर खो गया। मेरी परीक्षा 4 जुलाई को फतेहपुर में थी। टेट परीक्षा 2 से 4 जुलाई के मध्य हुई। बेटी संस्कृति की 2 जुलाई को चित्रकूट में परीक्षा हुई थी। प्रश्नपत्र देकर केंद्र से बाहर निकली संस्कृति के मुखमंडल में नन्हा सूरज चमक था। मुझे घर पर पढ़ता हुआ न देखकर परीक्षा के चार-पांच दिन पहले वह बोली कि पापा जी,मैं आपको कुछ आवश्यक टिप्स बता देती हूं। आप उतना पढ़ लें तो आराम से उत्तीर्ण हो जाएंगे, हालांकि मैं जानती हूं कि आप पास हो जाएंगे। बेटी के आग्रह पर गाइडों की खोजबीन शुरू हुई,पर वे नहीं मिलीं। पत्नी का स्वाभाविक गुस्सा चौथे आसमान पर था। वह संस्कृति से बोलीं कि बेटा पापा ने पांच मिनट भी किसी दिन गाईड खोलकर नहीं पढ़ा,बस अखबारों-पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते और दूसरी किताबें पढ़ते रहे हैं। मम्मी का तंज सुनकर बेटी विश्वास से मुस्कराती हुई बोली कि पापा की चिंता न करो,वह आसानी से पास हो जाएंगे। खैर,गाइडों का पैकेट 3 जुलाई की सुबह मिल गया। पैकेट में मोटी-मोटी चार गाईड देखकर पसीने छूट गये और खोलने की हिम्मत नहीं पड़ी। सिर चकराने लगा,तब गाइडों का पैकेट सिर के नीचे रखकर लेट गया और निद्रा ने अपने आगोश में ले लिया। इस बीच बेटी ने फोटो खींच कर परिवार के वाट्सऐप समूह में पोस्ट कर दिया और लिखा-टेट परीक्षा की गम्भीर पढ़ाई करते हुए पापा जी,अब सफलता दूर नही। तब मैंने वहां मजाकिया टिप्पणी की थी कि यह अध्ययन की अति प्राचीन अवशोषण विधा है,जिसमें लिखित सामग्री सीधे मस्तिष्क ग्रहण कर लेता है। यह विधा लुप्त हो गई थी,मैंने गहन शोध करके पुनः प्रकट किया है। वहां हंसी के गुब्बारे फूट रहे थे।

समय मुट्ठी में बंद रेत की मानिंद फिसलता रहा और परीक्षा का दिन आ पहुंचा। अनुज विनोद दीक्षित की कार द्वारा बांदा से दो अन्य शिक्षकों के साथ 4 जुलाई की सुबह परीक्षा देने फतेहपुर रवाना हुआ। दोनों सहयात्री शिक्षकों की बातचीत में गहरा दर्द रह-रहकर बाहर आ रहा था। मुझे लगा कि वह पीर-कसक-वेदना उनकी न होकर सम्पूर्ण शिक्षक समुदाय की हो गई है। समय से परीक्षा केंद्र पर पहुंच औपचारिकताएं पूरी कर बैग जमा किया और कक्ष में आवंटित अपनी सीट पर बैठ गया। वहां अन्यान्य शिक्षकों से भेंट और हंसी-मजाक का दौर चला पर हंसी की चादर के भीतर से पीड़ा अपना विद्रूप चेहरा निकाल बाहर झांक लेती थी तब माहौल यकायक उदास और नीरस हो जाता। घंटी बजी और ओएमआर शीट तथा प्रश्नपत्र दे दिया गया। ध्यानपूर्वक सभी पूर्तियां भरीं। स्टूडेंट लाइफ की फीलिंग आ रही थी। दिल धक-धक कर रहा था, गला सूख रहा था और कान गर्म होकर लाल हो रहे थे। हाथ जोड़ आराध्य हनुमान जी महाराज का स्मरण किया। पेपर खोलते ही उसमें ऐसा खोया कि समय का पता ही नहीं चला। एक बार रिचेक किया। आश्वस्त हुआ कि बहुत अच्छे नम्बर मिल जाएंगे। घंटी बजी,ओएमआर शीट जमा कर कक्ष से निकल जमा किया बैग लिया और बाहर निकल आया। उस दिन बहुत गर्मी थी, तेज तीखी धूप चेहरे पर चांटे मार रही थी। एक चाय की दूकान पर बैठ टिफिन निकाल पूड़ी सब्जी खा पानी पिया और फिर चाय ली। बहुत बढ़िया चाय थी,मन की थकान दूर हुई ताजगी आई।दूसरा प्रश्नपत्र भी ऐसा ही हुआ। वापस घर लौटकर एआई से जांचा तो प्राथमिक में 132 और उच्च प्राथमिक में 124 प्रश्न सही पाया। खाना खाकर सो गया।

और फिर,26 अगस्त की शाम को रिजल्ट आया। अगली सुबह रिजल्ट देखा तो बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए-प्राथमिक में 132 और जूनियर में 124 अंक। अब मैं सातवें आसमान पर हूं। मेरी सफलता की खुशी में उस दिन सुबह से ही वरुण देव के नयनों से अविराम अश्रु धारा प्रवाहित होती रही और विभाग ने रेनीडे घोषित कर दिया। और मैं,मैं पराठा सब्जी और एक गिलास दूध पीकर घर के सभी कार्यों से मुक्ति पाकर अपने अध्ययन कक्ष में पलंग पर बैठा यह संस्मरण लिख रहा हूं। साथियों के बधाई संदेश और फोन कॉल आ रहे हैं। पर मैं सोच रहा हूं कि बिना गाईड पढ़े पास कैसे हो गया।

लाल फीता

डॉ. सुरेश कुमार मिश्रा उरतृप्त

सदर तहसील के उस अंधेरे गलियारे में तीन टांगों के सहारे टिकी वह पुरानी लकड़ी की कुर्सी सालों से धूल फांक रही थी। वह कुर्सी दरअसल हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था का सजीव प्रतीक थी जिसमें स्थायित्व के लिए चौथे पाए की जगह ईंटों का एक चटखट्टा लगा हुआ था। ईंट और प्रशासन का पुराना रिश्ता है क्योंकि यहाँ फाइलें भी ईंट की रफ्तार से चलती हैं और अफ़सरों के दिल भी ईंट के ही बने होते हैं। पचहत्तर साल के जगन्नाथ बाबा हर सोमवार सुबह ठीक दस बजे अपने कांपते हाथों में एक लाल रंग की पुरानी फाइल दबाकर उस टूटी कुर्सी पर आकर बैठ जाते थे। दफ़्तर का नया चपरासी जब भी उन्हें वहाँ बैठते देखता तो झुंझलाकर कहता कि बाबा इस टूटी कुर्सी पर क्यों बैठते हो किसी दिन गिरकर अपनी बूढ़ी हड्डियां तुड़वा बैठोगे। चपरासी की यह चिंता मानवाधिकार से ज्यादा दफ़्तर की फर्श गंदी होने के डर से उपजी थी क्योंकि सरकारी फर्श पर बुजुर्ग का गिरना प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाता है। बाबा अपनी सूजी हुई आँखों से उसकी तरफ देखते और उदास मुस्कान बिखेरते हुए कहते कि बेटा इस कुर्सी से मेरी आत्मा का नाता जुड़ चुका है। असल में आत्मा और परमात्मा के मिलन के लिए भारत में सरकारी दफ़्तर से उपयुक्त कोई जगह नहीं है क्योंकि यहाँ पहुँचकर आदमी को दुनिया की नश्वरता का तुरंत आभास हो जाता है।

दफ़्तर के बड़े बाबू अक्सर उन्हें देखकर ताना मारते कि ज़मीन का मुआवज़ा पाना इतना आसान नहीं होता बूढ़े तुम तीन साल से यहाँ चक्कर काट रहे हो पर फाइल आगे सरकती ही नहीं। बड़े बाबू का यह कहना वैसा ही था जैसे यमराज किसी को अमर होने का वरदान दे रहे हों। सरकारी फाइल में पहिये नहीं होते पर उसके पैर इतने लंबे होते हैं कि वह दराज़ से निकलकर अलमारी तक पहुँचने में एक पूरी पीढ़ी निगल जाती है। तहसील में आने वाले तमाम फरियादी और मुंशी उस टूटी कुर्सी पर बैठे जगन्नाथ बाबा को बड़े अचरज से देखते थे जैसे वे किसी ऐतिहासिक स्मारक के अवशेष हों। बाबा कभी किसी अफ़सर से बदतमीज़ी नहीं करते थे क्योंकि वे जानते थे कि अफ़सर को गुस्सा दिलाना साक्षात् ईश्वर को त्यागपत्र देने जैसा है। दोपहर ढलते ही वे अपनी फाइल को झोले में रखते और कुर्सी के ईंट वाले पाए को थोड़ा सीधा करके अपने घर चले जाते थे। गाँव के लोग कहते थे कि बाबा की उपजाऊ ज़मीन पर जब से नया हाईवे बना है तब से वे एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए हैं। हाईवे दरअसल विकास की वह सड़क है जिस पर अमीर अपनी गाड़ियाँ दौड़ाते हैं और गरीब अपनी फाइलें।

जब भी कोई मुंशी या वकील बाबा से उनका दुखड़ा पूछने आता तो वे सिर्फ फाइल की तरफ इशारा करते। पूरा तहसील प्रशासन इस बात से हैरान था कि कोई इंसान बिना किसी उग्र प्रदर्शन के केवल एक टूटी कुर्सी पर बैठकर इतना गहरा सन्नाटा कैसे रच सकता है। असल में भारतीय प्रशासन को शोर की आदत है पर खामोशी उसे डराती है क्योंकि खामोश आदमी कभी भी रिश्वत की पेशकश नहीं करता। एक दिन अचानक ज़िले के नए कलेक्टर ने तहसील का औचक निरीक्षण किया। कलेक्टर साहब के आने का मतलब था कि धूल झाड़ी जाएगी और भ्रष्टाचार को थोड़ी देर के लिए अलमारी में बंद कर दिया जाएगा। कलेक्टर साहब ने जब बाबा को उस खस्ताहाल कुर्सी पर बैठे देखा तो गुस्से में चपरासी को डांटते हुए कहा... कि तुम लोग एक बुजुर्ग इंसान को इस टूटी कुर्सी पर बैठाकर उनकी जान से खिलवाड़ कर रहे हो। यह सरकारी संवेदनशीलता का वह क्षण था जब अफ़सर को कुर्सी की हालत देखकर दुख हुआ पर फाइल की हालत देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा।

जगन्नाथ बाबा तुरंत अपनी जगह से खड़े हो गए और गिड़गिड़ाते हुए बोले कि साहब जी मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है,इस टूटी कुर्सी को मत हटवाइए,यही तो मेरी आखिरी उम्मीद बची है। कलेक्टर साहब ने चकित होकर पूछा कि बाबा एक टूटी हुई सरकारी कुर्सी से आपकी ऐसी कौन सी उम्मीद बंधी हो सकती है। जगन्नाथ बाबा की आँखों से आंसुओं की धार बह निकली और वे कांपती आवाज़ में बोले कि साहब चार साल पहले मेरा बीस साल का बेटा इसी दफ़्तर में मुआवज़े के कागज़ जमा करने आया था और इसी टूटी कुर्सी पर बैठकर इंतज़ार करते करते भूखा प्यासा गिर पड़ा था जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी हमेशा के लिए टूट गई थी। यह सुनकर प्रशासन के कानों पर जूँ तो नहीं रेंगी पर कलेक्टर साहब की कुर्सी ज़रूर थोड़ी हिली। बाबा ने कहा कि उस दिन अफ़सरों ने कहा था कि जब तक यह कुर्सी यहाँ रहेगी तब तक तुम्हारे बेटे का मुआवज़ा अटका रहेगा। अफ़सरों की ज़ुबान और पत्थर की लकीर में बस इतना अंतर है कि पत्थर की लकीर मिट सकती है पर अफ़सर की अकर्मण्यता कभी नहीं बदलती।

मैं रोज़ यहाँ आकर इसी कुर्सी पर इसलिए बैठता हूँ ताकि इस दफ़्तर के बड़े अफ़सरों को याद रहे कि इस कुर्सी की एक टांग टूटने से मेरे घर का इकलौता सहारा अपाहिज हो गया। जिस व्यवस्था की अपनी टांग ईंट पर टिकी हो वह किसी बेसहारे का सहारा क्या बनेगी। यह सुनते ही पूरे तहसील परिसर में स्तब्धता छा गई जैसे किसी ने भ्रष्टाचार के मंदिर में सत्य का शंखनाद कर दिया हो। कलेक्टर साहब का सर शर्म से झुक गया जो कि एक दुर्लभ घटना थी क्योंकि आमतौर पर कलेक्टर का सर सिर्फ मंत्री के सामने झुकता है। उन्होंने तुरंत बाबा के झोले से फाइल निकाली और अपनी कलम से दस्तखत करते हुए रो पड़े। यह रोना शायद पश्चाताप का था या शायद इस बात का कि आज एक फाइल बिना किसी लेन देन के पूरी हो गई। जगन्नाथ बाबा ने उस स्वीकृत फाइल को सीने से लगाया और उस टूटी कुर्सी के पाए में लगी ईंट को सहलाते हुए बाहर की तरफ बढ़ गए। उन्होंने ईंट को ऐसे सहलाया जैसे वह कोई सरकारी पदक हो जो उन्हें सालों के इंतज़ार के बाद मिला था। बाहर उनका अपाहिज बेटा दवाइयों की राह देख रहा था और अंदर वह टूटी कुर्सी एक नई फाइल और एक नए बूढ़े का इंतज़ार करने लगी थी क्योंकि व्यवस्था बदलती नहीं बस अपना शिकार बदल लेती है।

शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्यता : शिक्षा की गुणवत्ता, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और सरकार की प्राथमिकता

वर्तमान समय में शिक्षकों के लिए टेट की अनिवार्यता का विषय केवल शिक्षकों की नौकरी या पदोन्नति तक सीमित नहीं है,

सुरेश कुमार साहू
रायपुर,छत्तीसगढ़

बल्कि यह सीधे-सीधे देश की शिक्षा व्यवस्था,बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार और भविष्य की पीढ़ी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण विषय है। आज भारत ही नहीं, बल्कि भारत के आस-पास के देशों में भी जेन-जी वर्ग सामाजिक एवं राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार,शिक्षा व्यवस्था और शासन की नीतियों पर सवाल उठाने वाला यह वर्ग सरकार को समय-समय पर आईना दिखाता है। इसलिए शिक्षा और शिक्षक नीति का कोई भी निर्णय व्यापक सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव डाल सकता है।ऐसे समय में जब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों के लिए भी टेट उत्तीर्ण करना आवश्यक माना गया है,तो सरकार के सामने मूल प्रश्न यह होगा कि टेट की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को कैसे बनाए रखा जाए।

यदि टेट जैसी राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा को कमजोर करके उसकी जगह केवल विभागीय टेट अथवा अत्यधिक सरल विभागीय परीक्षा के माध्यम से पात्रता प्रदान करने का रास्ता अपनाया जाता है,तो इससे टेट की मूल भावना और परीक्षा की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठ सकते हैं। किसी एक राज्य में ऐसा प्रयोग होने के बाद यदि दूसरे राज्य भी उसका अनुसरण करते हैं,तो इसका प्रभाव देश की शिक्षक पात्रता व्यवस्था और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ सकता है।

यह विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की भावना और बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अधिकार का मूल उद्देश्य योग्य एवं सक्षम शिक्षकों के माध्यम से बेहतर शिक्षा सुनिश्चित करना है। इसलिए किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था को इन मूल उद्देश्यों के अनुरूप ही होना चाहिए।सरकार के सामने दो महत्वपूर्ण पक्ष वर्तमान परिस्थितियों में सरकार के सामने मोटे तौर पर दो पक्ष दिखाई देते हैं। **पहला पक्ष** : वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की कठिनाइयों,सेवा-सुरक्षा और उनके हितों का संरक्षण। **दूसरा पक्ष** : बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा,शिक्षा व्यवस्था का स्तर,सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मूल भावना।सरकार के लिए चुनौती यही है कि वह दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाए,लेकिन अंततः सार्वजनिक हित और बच्चों के शिक्षा के अधिकार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे।

राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण विषय

यह भी एक सामान्य राजनीतिक तथ्य है कि शिक्षक वर्ग का एक बड़ा हिस्सा अपने अनुभव,विचारधारा और राजनीतिक समझ के आधार पर मतदान करता है। वहीं शिक्षित युवा एवं अन्य जागरूक वर्ग को कई बार फ्लोटिंग वोटर के रूप में देखा जाता है,जो मुद्दों और सरकार के कार्यों के आधार पर अपनी राजनीतिक पसंद बदल सकता है।इसलिए सरकार के सामने केवल किसी एक वर्ग को संतुष्ट करने का प्रश्न नहीं होगा, बल्कि उसे यह देखना होगा कि दीर्घकालीन रूप से शिक्षा व्यवस्था और व्यापक जनहित में कौन-सा निर्णय उचित है।मेरा मानना है कि सरकार अंततः ऐसा रास्ता चुनेगी जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता कमजोर न हो,टेट की विश्वसनीयता बनी रहे,सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान हो और बच्चों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के मौलिक अधिकार की रक्षा हो।हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने,अपनी बात सरकार और विभाग के सामने रखने तथा लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करने का पूरा अधिकार हैऔर आवश्यकता पड़ने पर संघर्ष करना भी चाहिए। लेकिन अंतिम निर्णय सरकार को किसी एक समूह के दबाव में नहीं,बल्कि संविधान, कानून, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, बच्चों के हित और व्यापक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर लेना होगा।इसीलिए वर्तमान परिस्थितियों में हमें संयम रखते हुए विश्वास रखना चाहिए कि अंततः वही व्यवस्था मजबूत होगी जो शिक्षक की गुणवत्ता,शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगी।शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं। योग्य शिक्षक,गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और बच्चों का उज्ज्वल भविष्य ही सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
सम्पादक

गुरुप्रीत सिंह सिद्धू पर हमले के बाद सियासत गरमाई,कांग्रेस ने एसपी से मांगी निष्पक्ष जांच...

जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा ज्ञापन,एफआईआर में संदिग्धों के नाम जोड़ने,हमले के कथित सूत्रधार की जांच और रासुका की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

कांग्रेस मंडल अध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह सिद्धू और उनकी पत्नी पर हुए कथित हमले को लेकर अंबिकापुर की सियासत गरमा गई है। सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक सरगुजा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने के साथ ही हमले में संदेह के दायरे में बताए जा रहे लोगों की भूमिका की जांच कर उनके नाम एफआईआर में जोड़ने की मांग की। 29 अगस्त की रात दरीपारा में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की है। उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के अनुसार मामले में चार आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी बताई गई है। घटना से संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है,जिसमें कई लोगों द्वारा मारपीट करते दिखाई देने की बात सामने आई है।

गुरुप्रीत रायपुर रेफर, आंख और सिर में चोट की बात

कांग्रेस की ओर से बताया गया कि हमले में घायल गुरुप्रीत सिंह सिद्धू का उपचार रायपुर के डीकेएस सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में चल रहा है। इससे पहले उन्हें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया था,जहां चिकित्सकीय परीक्षण के बाद बेहतर उपचार के लिए रायपुर रेफर किए जाने की जानकारी सामने आई थी। मीडिया रिपोर्टों में उनके सिर और आंख में गंभीर चोट का उल्लेख है। घटना के दौरान बीच-बचाव करने पहुंचीं उनकी पत्नी गुरुप्रीत कौर सिद्धू के साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है। इस घटनाक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता बड़ी संख्या में थाने पहुंचे थे।

प्रकाश साहू पर आरोप,भाजपा नेता ने नकारा...

कांग्रेस मंडल अध्यक्ष गुरुप्रीत सिंह सिद्धू ने हमले के पीछे भाजपा नेता प्रकाश साहू की भूमिका होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि हमले में शामिल बताए जा रहे कुछ लोग प्रकाश साहू के रिश्तेदार एवं व्यावसायिक सहयोगी हैं और इसलिए उनकी भूमिका की भी निष्पक्ष जांच जरूरी है। हालांकि,यह आरोप फिलहाल आरोप के स्तर पर ही हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार भाजपा नेता प्रकाश साहू ने हमले में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार करते हुए आरोपों को राजनीतिक रंजिश से प्रेरित बताया है।

कांग्रेस का सवाल...एफआईआर में नाम है तो जांच में भूमिका क्यों नहीं?

एसपी को सौंपे ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की कि मामले में केवल प्रत्यक्ष रूप से पकड़े गए लोगों तक जांच सीमित न रहे,बल्कि हमले से पहले और बाद में आरोपियों के संपर्क,मोबाइल कॉल डिटेल,सीसीटीवी फुटेज तथा घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भूमिका की भी जांच की जाए। निगम में नेता प्रतिपक्ष शफी अहमद ने हमले के दौरान कथित रूप से हमलावरों के संपर्क में रहे लोगों की पहचान किए जाने की मांग की,ताकि यदि किसी बड़े षड्यंत्र या साजिश की भूमिका हो तो उसका खुलासा हो सके।

'आदतन बदमाश' होने के कांग्रेस के आरोप की भी जांच की मांग

कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रकाश साहू के पुराने आपराधिक मामलों का हवाला देते हुए उनके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की मांग रखी। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्षी दल के नेताओं को जवाबदेह राजनीति करने के लिए सुरक्षा का भरोसा मिलना चाहिए। कांग्रेस ने पुलिस से यह भी सवाल किया कि यदि किसी व्यक्ति पर पूर्व में आपराधिक मामले रहे हैं तो उसकी वर्तमान गतिविधियों की निगरानी और कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से उसका रिकॉर्ड किस तरह देखा जा रहा है।

कांग्रेस बोली...राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए...

मीडिया से चर्चा में जिलाध्यक्ष बालकृष्ण पाठक ने कहा... कि इस मामले के साथ ही हाल के उन मामलों को भी विधानसभा में प्रश्न के रूप में उठाया जाएगा,जिनमें कांग्रेस के आरोप के अनुसार भाजपा से जुड़े लोगों की संलिप्तता सामने आई है और पुलिस पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया जा रहा है। वहीं प्रतिनिधिमंडल में शामिल भानुप्रताप सिंह और इरफान सिद्दीकी ने घटना में कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई जरूरी है,ताकि शहर में संगठित गुंडागर्दी और राजनीतिक संरक्षण की आशंका पर प्रभावी रोक लग सके।

पुलिस के सामने अब सबसे बड़ा सवाल...हमला विवाद था या सुनियोजित वारदात?

इस पूरे मामले में अब पुलिस जांच की दिशा महत्वपूर्ण हो गई है। उपलब्ध रिपोर्टों के मुताबिक प्रारंभिक विवाद वाहन खड़ा करने को लेकर शुरू होने की बात सामने आई है,जिसके बाद विवाद बढ़ा और कई लोग मौके पर पहुंचे। दूसरी ओर कांग्रेस इसे सुनियोजित हमला बता रही है। ऐसे में सीसीटीवी फुटेज,प्रत्यक्षदर्शियों के बयान,मोबाइल लोकेशन/कॉल रिकॉर्ड,घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भूमिका और दोनों पक्षों के आरोपों को आमने-सामने रखकर जांच करना ही पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकता है।

अब निगाहें पुलिस जांच पर...

क्या मामला सिर्फ आपसी विवाद और मारपीट तक सीमित था या इसके पीछे किसी सुनियोजित साजिश की कड़ियां भी जुड़ी हैं? इसका जवाब निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगा। ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में अरविंद सिंह,हेमंत तिवारी,विनय शर्मा,इंद्रजीत सिंह धंजल,विनीत विशाल जायसवाल,मैदान जायसवाल,शैलेन्द्र प्रताप सिंह,आशीष वर्मा,नरेंद्र विश्वकर्मा,जमील खान,जीवन यादव,आलोक सिंह,चंद्रप्रकाश सिंह,रजनीश सिंह,निकी खान,सतीश बारी,बल्केश्वर तिर्की,सौरभ फिलिप,अमित तिवारी राजा,आशीष जायसवाल,अविनाश कुमार,अमित सिंह,विकास शर्मा,मो. इमरान,तरणराज बाबरा,शिवांशु गुप्ता,अंकित जायसवाल सहित अन्य कांग्रेसजन मौजूद रहे।

सड़क पर अंधेरे में खड़ा था ट्रक,पीछे से जा भिड़ी बोलेरो खोपा धाम से लौट रहे एक श्रद्धालु की मौत,5 घायल

बारिश और अंधेरे के बीच सड़क पर खड़े ट्रक में नहीं था कोई संकेतक, घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

खोपा धाम से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की बोलेरो सड़क पर खड़े ट्रक से जा भिड़ी। हादसे में बोलेरो सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई,जबकि पांच अन्य लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में भर्ती कराया गया है। हादसा सोनवाही जंगल के पास हुआ। जानकारी के अनुसार सीतापुर क्षेत्र के ग्राम लिचिरमा से कुछ लोग बोलेरो वाहन में सवार होकर खोपा धाम गए थे। दर्शन के बाद सभी बोलेरो से वापस लौट रहे थे। इसी दौरान सोनवाही जंगल के पास मार्ग पर एक ट्रक खड़ा था। बताया जा रहा है कि ट्रक के खड़े होने का संकेत देने के लिए कोई संकेतक या अन्य चेतावनी व्यवस्था नहीं थी। वहीं रात का अंधेरा होने के साथ बारिश भी हो रही थी। बारिश और अंधेरे के कारण बोलेरो चालक सड़क पर खड़े ट्रक को समय रहते नहीं देख सका और वाहन सीधे ट्रक के पिछले हिस्से से जा टकराया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो में सवार लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। दुर्घटना में रतनपुर सीतापुर निवासी श्याम सुंदर (56),पिता स्वर्गीय रतिराम की मौत हो गई। वहीं बोलेरो में सवार सुभाष,मंजू,राजकुमारी, राजकुमार और सुशीला घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर लाया गया,जहां उन्हें भर्ती कर उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ट्रक सड़क पर लापरवाहीपूर्वक खड़ा किया गया था और उसके पीछे किसी प्रकार का संकेतक नहीं लगाया गया था। बारिश तथा अंधेरे के कारण सड़क पर खड़े ट्रक का अंदाजा बोलेरो चालक को नहीं लग सका और यह हादसा हो गया।

गला काटने की घटनाएं बढ़ीं,जटिल ऑपरेशन से 18 मरीजों को मिला जीवनदान

श्वास नली तक पहुंची चोटों में कान की उपास्थि से किया पुनर्निर्माण,सभी मरीज स्वस्थ

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

गले पर गंभीर और जानलेवा चोट के मामलों में लगातार बढ़ोतरी सामने आ रही है। राजमाता श्रीमती देवेंद्रकुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय से संबद्ध चिकित्सालय में इस वर्ष अब तक गले की गंभीर चोट से पहुंचे 18 मरीजों का सफल उपचार किया गया है। समय पर विशेषज्ञ चिकित्सा और जटिल सर्जरी के कारण सभी मरीजों की जान बचाई जा सकी है। मेडिकल कॉलेज के नाक-कान-गला (ईएनटी) विभाग के अनुसार वर्ष 2025 में गले की गंभीर चोट के 10 मरीज उपचार के लिए पहुंचे थे,जबकि वर्ष 2026 में अब तक यह संख्या बढ़कर 18 हो चुकी है। इनमें कई मरीजों की श्वास नली तक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी।

आधे मामले स्वयं को नुकसान पहुंचाने से जुड़े : ईएनटी विभाग के चिकित्सकों के अनुसार आपातकालीन कक्ष से पहुंचे लगभग आधे मामले स्वयं को नुकसान पहुंचाने से संबंधित रहे। वहीं अन्य मामले आपसी विवाद,रंजिश और हमले से जुड़े थे। अधिकतर मरीज 15 से 40 वर्ष आयु वर्ग के रहे हैं। हाल ही में गांधीनगर निवासी 21 वर्षीय छात्रा को गले में गंभीर चोट के बाद बेहद नाजुक हालत में अस्पताल लाया गया था। चिकित्सकों ने तत्काल उपचार शुरू कर ऑपरेशन किया। विशेषज्ञों की निगरानी में छात्रा की जान बचाई जा सकी। वर्तमान में वह स्वस्थ है और उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा काउंसलिंग भी दी जा रही है।

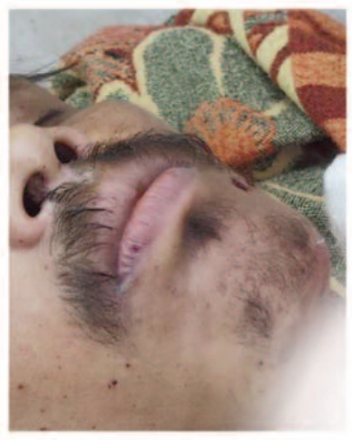

कान की उपास्थि से बनाई क्षतिग्रस्त श्वास नली : चिकित्सकों के अनुसार कुछ मरीजों में चोट इतनी गहरी थी कि श्वास नली का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। ऐसे जटिल मामलों में ईएनटी विशेषज्ञों ने कान की उपास्थि का उपयोग कर श्वास नली का पुनर्निर्माण किया। सर्जरी के बाद मरीजों की श्वास प्रक्रिया सामान्य हुई और सभी स्वस्थ हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि गले की चोट में सबसे बड़ा खतरा अत्यधिक रक्तस्राव और श्वास मार्ग बंद होने का होता है। ऐसे मामलों में शुरुआती कुछ मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। समय पर इलाज मिलने से मरीज की जान बचाई जा सकती है।

आधुनिक सुविधाओं से मिला उपचार : मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में उपलब्ध ब्लड बैंक,24 घंटे एनेस्थीसिया सेवा,ऑपरेशन थिएटर,वेंटिलेटर और क्रिटिकल केयर सुविधाओं ने गंभीर मरीजों के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शासन की व्यवस्था के तहत मरीजों को आवश्यक उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है।

तनाव के संकेतों को न करें नजरअंदाज : चिकित्सकों ने युवाओं में मानसिक तनाव,निराशा और पारिवारिक या शैक्षणिक दबाव को गंभीरता से लेने की अपील की है। यदि कोई व्यक्ति स्वयं को नुकसान पहुंचाने की बात करे,लोगों से दूरी बनाने लगे या असामान्य व्यवहार करे तो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। समय पर काउंसलिंग और विशेषज्ञ उपचार से गंभीर घटनाओं को रोका जा सकता है।

विशेषज्ञ टीम: ईएनटी विभाग के प्रो. डॉ. बीआर सिंह,प्रो. डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता,डॉ. अनुपम मिंज,डॉ. जीके दामले,डॉ. ऊषा आर्मो,डॉ. नेहा स्वर्णकार और डॉ. अदिति गोयल सहित चिकित्सकों की टीम गंभीर मरीजों का उपचार कर रही है।

विशेषज्ञ संदेश

'गले की गंभीर चोट में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। रक्तस्राव नियंत्रित करते हुए मरीज को जल्द से जल्द सक्षम अस्पताल पहुंचाना जीवन बचाने में सबसे अहम कदम है।'
प्रो. डॉ. शैलेन्द्र गुप्ता,वरिष्ठ चिकित्सक, ईएनटी विभाग, मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर.

1 सितंबर से केवरी पंचायत में शराब पर रोक,पीने-पिलाने पर लगेगा भारी जुर्माना

ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित,नशामुक्त पंचायत बनाने ग्रामीणों ने शुरू किया जनजागरूकता अभियान

-संवाददाता-
लखनपुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

नशे के खिलाफ लखनपुर विकासखंड के ग्राम पंचायत केवरी ने अनूठी पहल शुरू की है। पंचायत ने 1 सितंबर से गांव में शराब पीने, पिलाने और शराब के नशे में पहुंचने पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है। इसको लेकर पंचायत प्रतिनिधि, महिला समूह और ग्रामीण रैली निकालकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। ग्राम सभा में पारित प्रस्ताव के अनुसार गांव में शराब पीने पर 5 हजार रुपए,शराब बनाने और पिलाने पर 5 हजार रुपए तथा शराब के नशे में पाए जाने पर 3 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पंचायत की ग्राम सुधार समिति द्वारा घर-घर जाकर ग्रामीणों को नशे से दूर रहने की समझाइश दी जा रही है।

नशे से बढ़ रही थी घरेलू कलह

सरपंच मनिजर राम और ग्रामीणों ने बताया कि गांव में शराब की वजह से कई परिवार प्रभावित हो रहे थे। नशे की आदत से घरेलू विवाद बढ़ रहे थे और कई घर बर्बादी की ओर जा रहे थे। इसे देखते हुए पंचायत ने गांव को पूरी तरह नशामुक्त बनाने का निर्णय लिया है।

ग्रामीणों ने किया पहल का स्वागत

पंचायत की इस मुहिम में युवा,महिलाएं और पुरुष बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। जागरूकता रैली के दौरान ग्रामीणों ने अभियान का स्वागत करते हुए नशे से दूर रहने का संकल्प लिया। पंचायत का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और गांव को नशामुक्त बनाने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

नए जिला न्यायालय भवन के साथ अधिवक्ताओं के लिए 300 कक्ष और विश्राम गृह की मांग

करीब 1500 अधिवक्ताओं की जरूरतों को लेकर मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन,पार्किंग से इंटरनेट तक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

सरगुजा में नवीन जिला एवं सत्र न्यायालय भवन के निर्माण के साथ अब अधिवक्ताओं के लिए आवश्यक सुविधाओं को लेकर भी मांग उठी है। करीब 1500 अधिवक्ताओं की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिवक्ताओं के लिए पर्याप्त कार्यस्थल, आधुनिक पैरवी हॉल और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इस संबंध में कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने मुख्य न्यायाधीश,छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन क्रमांक 19/2026, दिनांक 28 अगस्त 2026 में नवीन न्यायालय भवन के साथ अधिवक्ताओं के लिए सुविधाओं को भी प्राथमिकता देने का आग्रह किया गया है।

300 कक्ष और आधुनिक पैरवी हॉल की मांग : ज्ञापन में लगभग 1500 अधिवक्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए पर्याप्त एवं आधुनिक पैरवी हॉल बनाने तथा अधिवक्ताओं के लिए अलग भवन में 300 कक्षों के निर्माण की मांग की गई है। तर्क दिया गया है कि अधिवक्ताओं को न्यायालयीन कार्य के दौरान बैठने और पैरवी की तैयारी के लिए व्यवस्थित स्थान मिलना जरूरी है।

बाहर से आने वाले वकीलों के लिए विश्राम गृह : सरगुजा जिले का न्यायिक क्षेत्र विस्तृत होने के कारण दूर-दराज से अधिवक्ताओं का अम्बिकापुर आना-जाना होता है। ऐसे में ज्ञापन में बाहर से आने वाले अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता विश्राम गृह बनाने की मांग भी रखी गई है।

पार्किंग,पानी,शौचालय और इंटरनेट की सुविधा : ज्ञापन में न्यायालय परिसर में पर्याप्त बैठने की व्यवस्था के साथ पार्किंग, पेयजल, शौचालय,कैंटीन एवं इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की गई है। अधिवक्ताओं का कहना है कि आधुनिक न्यायालय भवन के साथ सुविधाजनक कार्य वातावरण भी जरूरी है।

50 से 100 किमी तक आने वालों के लिए टोल में राहत : अम्बिकापुर एवं आसपास के क्षेत्रों से प्रतिदिन 50 से 100 किलोमीटर तक आवागमन करने वाले अधिवक्ताओं एवं नागरिकों की समस्या को भी ज्ञापन में उठाया गया है। इनके लिए टोल टैक्स में स्थानीय राहत दिलाने के लिए आवश्यक पहल करने का आग्रह किया गया है। ज्ञापन में अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता ने कहा कि नवीन न्यायालय भवन तभी पूर्ण अर्थों में सफल होगा,जब न्यायिक कार्य से जुड़े अधिवक्ताओं के लिए भी पर्याप्त और सम्मानजनक कार्य-सुविधाएं उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि मजबूत बार और बेहतर सुविधाएं मजबूत न्याय व्यवस्था की आधारशिला हैं।

चाचा के बीच-बचाव से भड़का भतीजा,बना हैवान

चाचा-चाची पर लोहे की रॉड और चाकू से ताबड़तोड़ हमला,आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेजा...

-संवाददाता-
राजपुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

पिता के साथ मारपीट रोकने से नाराज एक युवक ने अपने ही चाचा-चाची पर जानलेवा हमला कर दिया। राजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम चंद्रगढ़ में पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी ने घर में घुसकर दोनों पर लोहे की रॉड और चाकू से हमला किया। घटना में चाचा-चाची को गंभीर चोटें आई हैं। शिकायत के बाद राजपुर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 15 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

एक सप्ताह पहले हुआ था विवाद : पुलिस के अनुसार आरोपी शिवा गोंड (28) करीब एक सप्ताह पहले अपने पिता के साथ मारपीट कर रहा था। इस दौरान उसके चाचा ठाकुर प्रसाद गोंड ने बीच-बचाव कर मारपीट रोक दी थी। बताया जा रहा है कि इसी बात को लेकर शिवा अपने चाचा से नाराज था और मन में रंजिश रखे हुए था।

घर में घुसते ही गाली-गलौज,फिर हमला : आरोप है कि घटना के दिन शिवा गोंड चाचा के घर पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए विवाद करने लगा। देखते ही देखते उसने लोहे की रॉड और चाकू से चाचा-चाची पर हमला शुरू कर दिया। अचानक हुए हमले से दोनों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हमले में चाची की बांह और पीठ,जबकि चाचा के पीठ, पैर,जांघ और घुटने में चोटें आईं। घटना के बाद आसपास के लोगों में भी हड़कंप मच गया।

आदिवासी कला केंद्र मैदान को व्यावसायिक परिसर में बदलने का विरोध

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ने राज्यपाल,मुख्यमंत्री और कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन....

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज सरगुजा ने अंबिकापुर स्थित आदिवासी कला केंद्र मैदान को व्यावसायिक परिसर एवं पार्क में तब्दील किए जाने का विरोध किया है। समाज के पदाधिकारियों ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री,अनुसूचित जनजाति मंत्री और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर मैदान को यथावत रखने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरगुजा जिला संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में आता है। यहां आदिवासी समाज की लोक कला,संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण के लिए आदिवासी कला केंद्र मैदान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। समाज के पदाधिकारियों का कहना है कि इस मैदान में वर्षों से आदिवासी समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और पारंपरिक कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। नगर निगम द्वारा इसे व्यावसायिक परिसर एवं पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है, जिससे आदिवासी समाज की सांस्कृतिक विरासत प्रभावित होगी।

पूर्वजों की विरासत से जुड़ा है मैदान : ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि यह स्थान सरगुजा की आदिवासी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। यहां मांदर,ढोल और झांझ के साथ पारंपरिक नृत्य एवं गायन कार्यक्रम आयोजित होते रहे हैं। इसी कारण इस स्थान का नाम आदिवासी कला केंद्र मैदान रखा गया। समाज ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51 (क) एवं (ख) के तहत देश की संस्कृति और विरासत का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों की परंपराओं और संस्कृति की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।

मैदान को यथावत रखने की मांग : सर्व आदिवासी समाज ने मांग की है कि आदिवासी कला केंद्र मैदान को किसी भी व्यावसायिक उपयोग में नहीं बदला जाए।

CMYK

जहां कोई जाता नहीं,वहां विकास दौड़ पड़ा! खुटरापारा में लाखों की पुलिया-रास्ता किसे जोड़ती है,शायद फाइल भी नहीं जानती

जिस रास्ते पर आवाजाही नहीं...वहां 10 लाख से अधिक खर्च...निजी जमीन पर निर्माण के आरोप ने बढ़ाई पंचायत की मुश्किल...

न रास्ता आबाद,न जरूरत साफ...फिर भी लाखों की पुलिया! खुटरापारा में सरकारी धन के इस्तेमाल पर सवाल...

खुटरापारा में विकास' की उलटी गंगा, निजी जमीन पर लाखों की पुलिया!

पंचायत में पहले पुलिया बनी,अब जरूरत तलाश रहे सवाल! खुटरापारा का मनरेगा निर्माण घेरे में...

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

पंचायतों में विकास कार्य इसलिए किए जाते हैं ताकि गांव की जरूरतें पूरी हों,लोगों का आवागमन आसान हो और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुंचे,लेकिन जब विकास की प्राथमिकता जरूरत के बजाय निर्माण और खर्च बन जाए,तब वही निर्माण सवालों के घेरे में आ जाता है,कोरिया जिले के बैकुंठपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत खुटरापारा में मनरेगा से कराए गए आरसीसी पुलिया निर्माण को लेकर सामने आए दस्तावेज और मौके की तस्वीरें इसी तरह के कई सवाल खड़े कर रही हैं। मामला करीब 10.07 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति वाले आरसीसी पुलिया निर्माण से जुड़ा है,सरकारी सूचना पटल पर कार्य का विवरण,स्वीकृत राशि, मजदूरी और सामग्री मद सहित अन्य जानकारियां दर्ज हैं,लेकिन दूसरी तरफ इस निर्माण की जरूरत, उपयोगिता और निर्माण स्थल की भूमि को लेकर शिकायत सामने आ चुकी है,सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस रास्ते पर सामान्य ग्रामीण आवागमन ही नहीं के बराबर बताया जा रहा है,वहां लाखों रुपये खर्च कर पुलिया आखिर किस जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई?

'पुल किसे जोड़ता है?' सबसे बड़ा सवाल...

मौके की स्थिति को देखकर एक और सवाल उठता है कि आखिर यह पुलिया किस गांव, किस बस्ती या किस मुख्य मार्ग को जोड़ने के लिए बनाई गई है? किसी पुलिया का निर्माण अपने आप में विकास नहीं है,उसकी उपयोगिता तभी है जब वह किसी वास्तविक आवागमन की समस्या का समाधान करे,यदि पुलिया बनने के बाद भी उसका इस्तेमाल करने वाला कोई प्रमुख मार्ग नहीं है,तो फिर यह सवाल उठेगा कि योजना तैयार करते समय आवश्यकता का आकलन किस आधार पर किया गया था,क्या ग्रामसभा में इस कार्य की आवश्यकता पर चर्चा हुई थी? क्या ग्रामीणों से प्रस्ताव लिया गया था? क्या स्थल का तकनीकी निरीक्षण हुआ था? क्या यह देखा गया कि बरसात में यहां वास्तव में आवागमन बाधित होता है? इन सवालों के जवाब कार्य की स्वीकृति फाइल से मिल सकते हैं।

निजी जमीन पर सरकारी निर्माण का आरोप...

मामले का दूसरा और अधिक गंभीर पहलू भूमि स्वामित्व से जुड़ा है, 25 मई 2026 को जनदर्शन अधिकारी के समक्ष दिए गए आवेदन में लवांगो बाई, पति हीरसाय, ग्राम खुटरापारा की ओर से शिकायत की गई है कि जिस भूमि पर ग्राम पंचायत एजेंसी द्वारा आरसीसी पुलिया निर्माण कराया जा रहा है,उस भूमि पर उनका स्वामित्व एवं आधिपत्य है,शिकायत में खसरा नंबर 42/4 एवं 42/5 सहित भूमि का उल्लेख किया गया है,शिकायतकर्ता का कहना है कि उनकी सहमति के बिना पंचायत द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा है और इस कारण निर्माण रोककर मामले की जांच की जाए,यदि शिकायत में किया गया दावा सही है तो मामला केवल अनावश्यक निर्माण तक सीमित नहीं रहेगा,तब सवाल यह होगा कि निजी भूमि की स्थिति की जांच किए बिना सरकारी योजना का निर्माण स्थल कैसे निर्धारित हुआ?

विकास के नाम पर निर्माण या निर्माण के नाम पर खर्च?...ग्रामीण विकास योजनाओं का मूल उद्देश्य स्पष्ट है-जहां सड़क की जरूरत है वहां सड़क,जहां जल निकासी की जरूरत है वहां नाली और जहां बरसात में आवागमन बाधित होता है वहां पुलिया बनाई जाए,लेकिन यदि किसी ऐसे रास्ते पर पुलिया बना दी जाए जिसका उपयोग ही सीमित हो,तो उसकी उपयोगिता पर सवाल उठना स्वाभाविक है,खुटरापारा की इस पुलिया को लेकर स्थानीय स्तर पर यही सवाल उठाया जा रहा है,बताया जा रहा है कि जिस मार्ग पर निर्माण किया गया,वहां से न तो कोई प्रमुख ग्रामीण मार्ग जुड़ता दिखाई देता है और न ही ऐसा नियमित आवागमन है,जिससे दस लाख रुपये से अधिक के निर्माण को तत्काल आवश्यक माना जा सके,ऐसे में पंचायत को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस पुलिया से कितने ग्रामीण परिवार लाभान्वित होंगे,यह किस आबादी को जोड़ती है और इस मार्ग की प्राथमिकता तय करने का आधार क्या था? क्योंकि सरकारी योजना में किसी कार्य का स्वीकृत हो जाना और उसका वास्तव में जनहित में जरूरी होना–दो अलग-अलग बातें हैं।

राजस्व रिकॉर्ड बनाम पंचायत की फाइल-मामले से जुड़े राजस्व दस्तावेजों में संबंधित खसरों का विवरण दिखाई देता है, दस्तावेजों में खसरा नंबर 42/4, 42/5 सहित अन्य भूमि खंडों का उल्लेख है,यहीं पर प्रशासन के सामने जांच का सबसे आसान रास्ता भी मौजूद है,राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि की सीमा का मौके पर सीमांकन कराया जाए और यह देखा जाए कि पुलिया वास्तव में किस खसरे में बनी है,इसके बाद पंचायत की कार्य स्वीकृति और तकनीकी नक्शे से उसका मिलान किया जाए,यदि तीनों रिकॉर्ड–राजस्व नक्शा,पंचायत की स्वीकृति और मौके की वास्तविक स्थिति–एक-दूसरे से मेल खाते हैं तो विवाद काफी हद तक स्पष्ट हो सकता है, लेकिन यदि निर्माण स्थल और स्वीकृत स्थल अलग पाए जाते हैं,या निजी भूमि पर निर्माण की पुष्टि होती है,तो फिर जिम्मेदारी तय करने का प्रश्न सामने आएगा।

सूचना पटल पर खर्च का हिसाब, लेकिन उपयोगिता का हिसाब कौन देगा?-मौके पर लगे नागरिक सूचना पटल पर कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति करीब 10.07 लाख रुपये बताई गई है,इसमें मजदूरी और सामग्री मद की राशि भी दर्ज है। सूचना पटल के अनुसार कार्य प्रारंभ की तारीख 24 दिसंबर 2024 दर्ज है,यानी सरकारी रिकॉर्ड में कार्य का हिसाब मौजूद है,लेकिन सवाल यह है कि सरकारी पैसे के खर्च का हिसाब तो सूचना पटल बता रहा है,इस खर्च की उपयोगिता का हिसाब कौन देगा? यदि पुलिया जरूरी थी तो उसके उपयोग का स्पष्ट आधार होना चाहिए, यदि रास्ता ग्रामीणों की आवश्यकता के कारण चुना गया था तो कितने परिवार इससे लाभान्वित होते हैं, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए।

मनरेगा में 'काम दिखना' ही पर्याप्त नहीं-मनरेगा के कार्यों में मजदूरी रोजगार के साथ स्थायी परिसंपत्ति निर्माण का उद्देश्य भी जुड़ा है,इसलिए किसी कार्य का सिर्फ जमीन पर दिखाई देना पर्याप्त नहीं है,यह भी जरूरी है कि वह टिकाऊ,उपयोगी और वास्तविक जरूरत पर आधारित हो,यदि किसी पंचायत में बजट उपलब्ध है और उसे खर्च करने के लिए ऐसे निर्माण किए जाते हैं जिनकी उपयोगिता सीमित है,तो इससे वास्तविक जरूरत वाले गांव और परिवार पीछे छूट सकते हैं,यही कारण है कि खुटरापारा की पुलिया की जांच केवल तकनीकी गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहनी चाहिए,कार्य की आवश्यकता,स्थल चयन, भूमि स्वामित्व, ग्रामसभा की प्रक्रिया और भुगतान रिकॉर्ड सभी पहलुओं की जांच जरूरी है।

अब संयुक्त जांच ही बताएगी सच-इस पूरे मामले में सबसे उचित कदम संयुक्त स्थल जांच और दस्तावेजी मिलान होगा, राजस्व विभाग को भूमि का सीमांकन करना चाहिए,जनपद पंचायत और मनरेगा के तकनीकी अधिकारियों को कार्य की स्वीकृति और स्थल का परीक्षण करना चाहिए,पंचायत से ग्रामसभा प्रस्ताव और कार्य चयन का रिकॉर्ड लिया जाना चाहिए,इसके साथ ही कार्य की तकनीकी स्वीकृति,प्रशासकीय स्वीकृति,माप पुस्तिका,जियो-टैग तस्वीरें,मजदूरी भुगतान, सामग्री भुगतान और कार्य पूर्णता संबंधी दस्तावेज की जांच की जानी चाहिए,इससे यह साफ हो सकता है कि पुलिया वास्तव में स्वीकृत स्थान पर बनी है या नहीं और निर्माण का वास्तविक जनहित क्या था।

शिकायतें पहले भी पहुंचीं,फिर मामला क्यों नहीं सुलझा?

इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भूमि और निर्माण को लेकर शिकायत पहली बार नहीं की गई थी, शिकायतकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन में उल्लेख है कि पूर्व में भी संबंधित अधिकारियों के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई गई थी,इसमें 6 जनवरी 2025 को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी,22 फरवरी 2025 को तहसीलदार बैकुंठपुर तथा 15 अप्रैल 2025 को जनदर्शन में आवेदन दिए जाने का उल्लेख है,शिकायत में यह भी कहा गया है कि आपत्ति के बाद निर्माण कार्य लंबे समय तक बंद रहा,लेकिन बाद में फिर से निर्माण कार्य शुरू करने का प्रयास किया गया,यही बिंदु प्रशासनिक जांच को और जरूरी बनाता है,यदि शिकायत के बाद कार्य रोका गया था तो उस समय क्या जांच हुई? क्या भूमि विवाद का निराकरण किया गया? क्या शिकायतकर्ता की आपत्ति खारिज की गई? क्या कोई सीमांकन रिपोर्ट बनी? क्या निर्माण स्थल बदलने या काम जारी रखने का कोई आदेश दिया गया? इन सवालों का जवाब संबंधित विभागीय रिकॉर्ड से ही मिलेगा।

सवाल पुलिया से बड़ा है...

खुटरापारा की पुलिया का विवाद केवल एक निर्माण कार्य का मामला नहीं है। यह पंचायतों में विकास की प्राथमिकता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है,क्या पहले जरूरत तय होती है और फिर निर्माण होता है,या पहले निर्माण तय होता है और बाद में जरूरत खोजी जाती है? यदि पुलिया जरूरी थी तो पंचायत को जनता के सामने उसका पूरा औचित्य रखना चाहिए,यदि निजी भूमि का आरोप गलत है तो राजस्व रिकॉर्ड और सीमांकन से स्थिति साफ की जा सकती है,और यदि शिकायत सही पाई जाती है तो यह भी तय होना चाहिए कि सरकारी योजना का स्थल चयन किस स्तर पर गलत हुआ,सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि 10 लाख रुपये से अधिक की राशि से बनी या बनाई जा रही परिसंपत्ति का उपयोग वर्षों तक होना चाहिए,केवल सरकारी फाइल में उसका निर्माण पूरा दिखना पर्याप्त नहीं है,खुटरापारा में अब गेंद प्रशासन के पाले में है,जमीन का सीमांकन,पुलिया की उपयोगिता और मनरेगा की पूरी फाइल...इन तीनों की निष्पक्ष जांच हो जाए तो यह साफ हो जाएगा कि यहां विकास हुआ है या फिर'निर्माण के लिए निर्माण'की कहानी लिखी गई है।

अगस्त में 658 मिमी वर्षा,1969 के बाद दूसरी सबसे अधिक बारिश,लगातार तीसरे दिन बरसे बदरा

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

चार माह की मानसूनी अवधि पूरी होने से पहले ही अंबिकापुर में औसत बारिश का आंकड़ा पार हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 31 अगस्त तक अंबिकापुर में कुल 1229.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो मानसून की सामान्य औसत वर्षा 1220 मिमी का 100.8 प्रतिशत है। यानी मानसून के अभी करीब एक माह शेष रहते ही सामान्य बारिश का लक्ष्य पूरा हो चुका है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार मानसून की अवधि कुल 122 दिन यानी चार माह की होती है। सोमवार को मानसून के 92 दिन पूरे हुए हैं। इसके बावजूद अंबिकापुर में अब तक सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। जून से अगस्त तक तीन महीनों में ही अच्छी बारिश होने से जिले में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला हुआ है।

अगस्त में रिकॉर्ड बारिश,55 साल बाद दूसरा बड़ा आंकड़ा

इस वर्ष अगस्त माह में बारिश ने नया रिकॉर्ड बनाया है। मौसम विभाग के अनुसार अगस्त में कुल 658 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जो वर्ष 1969 के बाद अगस्त माह में दूसरी सबसे अधिक बारिश है। इससे पहले अगस्त माह में इतनी अधिक बारिश का आंकड़ा कभी-कभार ही दर्ज हुआ है। अगस्त के अंतिम सप्ताह में लगातार सक्रिय रहे मानसूनी सिस्टम के कारण जिले में रुक-रुककर तेज बारिश का दौर जारी रहा।

जुलाई में भी जमकर बरसे बादल

मानसून की शुरुआत में जून माह में बारिश सामान्य से कम रही और पूरे महीने में 109.3 मिमी वर्षा दर्ज की गई। इसके बाद जुलाई में मानसून पूरी तरह सक्रिय हुआ और 462 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई। अगस्त में बारिश की रफ्तार और बढ़ गई। तीनों महीनों की बारिश को मिलाकर अब तक 1229.3 मिमी पानी गिर चुका है।

किसानों को राहत,जलभराव की स्थिति भी बनी

अच्छी बारिश से जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है। धान सहित खरीफ फसलों के लिए पर्याप्त पानी मिलने से खेती-किसानी का काम तेजी से चल रहा है। हालांकि लगातार बारिश के कारण कुछ क्षेत्रों में खेतों में पानी भरने और शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अभी सक्रिय स्थिति में है। अगले कुछ दिनों तक सरगुजा संभाग में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। अगस्त के अंतिम दिनों में हुई बारिश ने जिले के मानसूनी आंकड़ों को मजबूत कर दिया है। अब लोगों की नजर सितंबर माह में होने वाली बारिश पर है, जिससे वर्षा का कुल आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है।

निर्धारित किराए से ज्यादा वसूली पर परिवहन विभाग की कार्रवाई,यात्रियों को लौटाई अतिरिक्त राशि

अम्बिकापुर-रामानुजगंज और बिलासपुर रूट पर जांच में सामने आया मामला,दो बसों पर चालानी कार्रवाई

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

यात्री बसों में निर्धारित दर से अधिक किराया वसूले जाने की शिकायतों को परिवहन विभाग ने गंभीरता से लेते हुए बस स्टैंड अम्बिकापुर में जांच अभियान चलाया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के निर्देश पर परिवहन उड़नदस्ता प्रभारी आसम्भर द्विवेदी के नेतृत्व में यात्री बसों की जांच की गई। इस दौरान अधिकारियों ने बसों में सफर कर रहे यात्रियों से सीधे किराए की जानकारी ली और निर्धारित दर से अधिक राशि वसूले जाने पर यात्रियों को अतिरिक्त राशि वापस कराई।

रामानुजगंज रूट पर अतिरिक्त किराया वापस

जांच के दौरान अम्बिकापुर से रामानुजगंज जाने वाली साधारण बस में यात्रियों से किराए की जानकारी ली गई। निर्धारित दर से अधिक किराया लिए जाने की स्थिति सामने आने पर परिवहन विभाग ने संबंधित यात्रियों को अतिरिक्त वसूली गई राशि वापस कराई।

बिलासपुर जाने वाले यात्रियों को भी मिली राहत

इसी तरह बिलासपुर रूट पर संचालित साधारण बसों की जांच में यात्रियों से 400 रुपए किराया लिए जाने की जानकारी सामने आई। निर्धारित दर से अधिक वसूली पाए जाने पर अतिरिक्त राशि यात्रियों को वापस कराई गई। परिवहन विभाग की मौके पर की गई कार्रवाई से यात्रियों को राहत मिली और बस संचालकों को भी निर्धारित किराए के पालन के संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए।

किराया सूची नहीं लगाने पर दो बसों पर कार्रवाई...

जांच के दौरान दो बसों में किराया सूची चस्पा नहीं करने और निर्धारित दर से अधिक किराया लेने का मामला सामने आया। परिवहन विभाग द्वारा दोनों बसों के विरुद्ध नियमानुसार चालानी कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने बस संचालकों को निर्देशित किया कि प्रत्येक यात्री बस में किराया सूची प्रमुख स्थान पर अनिवार्य रूप से चस्पा की जाए,ताकि यात्रियों को निर्धारित किराए की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सके।

रायपुर रूट पर निर्धारित किराया मिला

परिवहन उड़नदस्ता द्वारा रायपुर की ओर संचालित बसों की भी जांच की गई। जांच के दौरान इन बसों में निर्धारित दर के अनुसार किराया लिया जाना पाया गया।

मनमाना किराया वसूली बर्दाश्त नहीं...

परिवहन विभाग ने बस संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यात्रियों से निर्धारित दर से अधिक किराया नहीं लिया जाए। यात्रियों को किराए की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बसों में किराया सूची चस्पा करना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने कहा गया है।

यात्रियों के हक में कार्रवाई...

परिवहन विभाग की इस कार्रवाई को यात्रियों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निर्धारित किराए से अधिक राशि वसूले जाने की स्थिति में मौके पर ही अतिरिक्त राशि वापस कराना इस बात का संकेत है कि यात्रियों से मनमाना किराया वसूलने वालों पर विभाग की नजर है। यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे बस में यात्रा करने से पहले किराया सूची जरूर देखें और निर्धारित दर से अधिक किराया लिए जाने पर संबंधित परिवहन विभाग को शिकायत करें।

CMYK

तरईया नदी का पुल क्षतिग्रस्त, कोटाडोल-कमर्जी मार्ग बंद

7 सितंबर तक आवागमन पर रोक, प्रशासन ने जारी किया डायवर्जन रूट; उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

कोटाडोल से महज 300 मीटर दूर है क्षतिग्रस्त पुल

17 की जगह 24 किलोमीटर होगा सफर

कई पंचायतें और सीमावर्ती गांव प्रभावित

प्रतिबंधित पुल से गुजरने पर होगी कार्रवाई
BNS की धारा 223 और मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 179(1), 184 एवं 194(1) के तहत कार्रवाई संभव

30 अगस्त से 7 सितंबर तक लागू रहेगा आदेश

तरईया पुल टूटा,रास्ता बंद...अब 17 की जगह 24 किमी का सफर

तरईया पुल क्षतिग्रस्त,कोटाडोल-कमर्जी आवागमन पर ब्रेक

कोटाडोल-कमर्जी मार्ग पर आवागमन प्रतिबंधित...7 सितंबर तक डायवर्जन...उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई...

प्रशासन ने जारी किया डायवर्जन रूट, 7 सितंबर तक प्रतिबंध, उल्लंघन पर कहर और मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई...

कोटाडोल से महज 300 मीटर दूर है पुल,डायवर्जन से 17 की जगह 24 किलोमीटर करना होगा सफर,कई पंचायतों और सीमावर्ती गांवों पर असर

राजन पाण्डेय

कोरिया/एमसीबी,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

मानसून की लगातार बारिश के बीच कोरिया और मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर क्षेत्र में सड़क और पुल-पुलियों की स्थिति अब चिंता का विषय बनने लगी है,कोटाडोल-कमर्जी मुख्य मार्ग पर तरईया नदी का पुल 30 अगस्त 2026 को क्षतिग्रस्त हो गया,पुल की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इस मार्ग पर सभी प्रकार के आवागमन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है,उप-विभागीय मजिस्ट्रेट, भरतपुर द्वारा जारी आदेश के बाद अब पैदल यात्रियों से लेकर दोपहिया और अन्य वाहनों के लिए भी पुल का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किया है,हालांकि डायवर्जन के कारण कोटाडोल और कमर्जी के बीच पहले की करीब 17 किलोमीटर दूरी बढ़कर लगभग 24 किलोमीटर हो जाएगी,यानी लोगों को करीब सात किलोमीटर अतिरिक्त सफर करना पड़ेगा,क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और लगातार बारिश को देखते हुए यह अतिरिक्त दूरी ग्रामीणों और नियमित यात्रियों के लिए परेशानी बढ़ाने वाली साबित हो सकती है।

पैदल से लेकर दोपहिया और वाहनों तक रोक...

जारी आदेश के तहत क्षतिग्रस्त पुल से पैदल यात्रियों,मोटरसाइकिल,स्कूटर सहित दोपहिया वाहनों तथा हल्के और भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है,प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित पुल को पार करने की कोशिश करने के बजाय निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का इस्तेमाल किया जाए,विशेष रूप से बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त पुल को पार करना जान जोखिम में डालने जैसा हो सकता है,यहां प्रशासन की चुनौती केवल पुल बंद कराने तक सीमित नहीं है,ग्रामीणों को डायवर्जन मार्ग की जानकारी देना और यह सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा कि लोग सुविधा या दूरी कम करने के प्रयास में प्रतिबंधित पुल का इस्तेमाल न करें।

जनकपुर की ओर से आने वालों के लिए यह होगा डायवर्जन

पुल बंद होने के बाद जनकपुर की ओर से आने वाले पैदल यात्रियों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किया गया है,उन्हें ग्राम बरौता से ग्राम नेरुवा,ग्राम रजरावल होते हुए खिरकी वन विभाग बैरियर तक पहुंचना होगा,इसके बाद निर्धारित मार्ग से आगे आवागमन किया जा सकेगा,प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक मार्ग का कुछ हिस्सा कच्चा है,लगातार बारिश की स्थिति में ऐसे रास्तों पर फिसलन और कीचड़ की समस्या हो सकती है,इसलिए यात्रियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत होगी,डायवर्जन मार्ग का उद्देश्य लोगों को क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर तत्काल सुरक्षित आवागमन की सुविधा देना है,इसलिए प्रशासन ने लोगों से निर्धारित मार्ग का ही उपयोग करने की अपील की है।

कोटाडोल से महज 300 मीटर दूर है पुल-तरईया नदी पर स्थित यह पुल कोटाडोल से लगभग 300 मीटर की दूरी पर है,जबकि खिरकी बैरियर करीब दो किलोमीटर दूर बताया गया है। यह क्षेत्र ग्राम पंचायत कोटाडोल के अंतर्गत आता है और कोटाडोल-कमर्जी मार्ग स्थानीय आवागमन के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जाता है,पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद इस मार्ग से गुजरने वाले ग्रामीणों,दोपहिया वाहन चालकों और अन्य यात्रियों के सामने तत्काल वैकल्पिक रास्ते की समस्या खड़ी हो गई,बारिश के मौसम में नदी और पुल पर बढ़ते जलस्तर तथा क्षतिग्रस्त संरचना को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी तरह का जोखिम लेने के बजाय मार्ग बंद करने का निर्णय लिया है,प्रशासन का मानना है कि क्षतिग्रस्त पुल से आवागमन जारी रहने पर पुल के और अधिक क्षतिग्रस्त होने के साथ दुर्घटना की आशंका बनी रह सकती है, इसी वजह से आगामी आदेश तक पुल से आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है।

कमर्जी की ओर से आने वालों को भी बदलना होगा रास्ता-इसी तरह कमर्जी की ओर से आने वाले यात्रियों को भी तरईया पुल की तरफ जाने की अनुमति नहीं होगी,उन्हें खिरकी वन विभाग बैरियर से निर्धारित वैकल्पिक मार्ग अपनाना होगा,इस मार्ग में रजरावल, नेरुवा और बरौता होते हुए आगे बढ़ने की व्यवस्था की गई है,प्रशासन द्वारा निर्धारित इस वैकल्पिक व्यवस्था में फिलहाल पैदल यात्रियों,दोपहिया वाहनों और आपातकालीन एंबुलेंस सेवाओं को आवागमन की अनुमति दी गई है,वहीं भारी तथा अन्य वाहनों के लिए इस मार्ग को अनुमति नहीं दी गई है,इसका सीधा अर्थ यह है कि बड़े वाहनों को फिलहाल दूसरे विकल्प तलाशने होंगे,इससे माल परिवहन और नियमित व्यावसायिक आवाजाही पर भी असर पड़ने की संभावना है।

17 किलोमीटर से बढ़कर 24 किलोमीटर हुआ सफर-तरईया पुल बंद होने का सबसे प्रत्यक्ष असर कोटाडोल-कमर्जी के बीच यात्रा की दूरी पर पड़ेगा,पहले दोनों स्थानों के बीच दूरी करीब 17 किलोमीटर थी,अब डायवर्जन मार्ग के कारण यात्रियों को लगभग 24 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी,यानी लोगों के सफर में लगभग सात किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी जुड़ गई है,ग्रामीण क्षेत्र में जहां रोजमर्रा के काम,बाजार,स्वास्थ्य सुविधा,शिक्षा और अन्य आवश्यकताओं के लिए लोगों को नियमित आवागमन करना पड़ता है,वहां सात किलोमीटर अतिरिक्त दूरी भी महत्वपूर्ण होती है,बारिश के मौसम में यदि डायवर्जन का हिस्सा कच्चा है तो समय और परेशानी दोनों बढ़ सकते हैं,फिर भी प्रशासन के सामने फिलहाल सबसे बड़ी प्राथमिकता सुरक्षा है,क्षतिग्रस्त पुल पर आवागमन की अनुमति देकर किसी दुर्घटना का जोखिम उठाने के बजाय वैकल्पिक रास्ता अपनाना ही सुरक्षित विकल्प माना गया है।

प्रतिबंध तोड़ा तो होगी कानूनी कार्रवाई-प्रशासन ने केवल पुल बंद करने का आदेश जारी नहीं किया है,बल्कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी है,जारी आम सूचना के अनुसार प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई व्यक्ति क्षतिग्रस्त पुल से आवागमन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता,2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जा सकती है,इसके अलावा वाहन चालकों द्वारा प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 179(1),184 और 194(1) के तहत अर्थदंड एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है,प्रशासन का संदेश स्पष्ट है कि पुल बंद करने का फैसला महज औपचारिकता नहीं है,प्रतिबंधित मार्ग से गुजरने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

7 सितंबर तक प्रभावी रहेगा आदेश-उप-विभागीय मजिस्ट्रेट,भरतपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा 163 के तहत 30 अगस्त 2026 को आदेश जारी किया गया है,आदेश के अनुसार पुल पर लगाया गया प्रतिबंध 7 सितंबर 2026 तक या प्रशासन द्वारा इससे पहले आदेश को निरस्त अथवा संशोधित किए जाने तक प्रभावी रहेगा,इसका मतलब यह है कि 7 सितंबर तक लोगों को निर्धारित वैकल्पिक मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा,जब तक कि प्रशासन पुल की स्थिति का आकलन करने के बाद कोई नया आदेश जारी नहीं करता।

कई पंचायतों और सीमावर्ती क्षेत्र पर असर-कोटाडोल-कमर्जी मार्ग केवल दो गांवों के बीच का रास्ता नहीं है,इस मार्ग से जुड़े आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों और पंचायतों के लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही भी प्रभावित होगी,मध्यप्रदेश सीमा से लगे क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग का महत्व और बढ़ जाता है,सीधी,बैढ़न अथवा आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाले लोगों को भी मार्ग बंद होने से अतिरिक्त दूरी और समय का सामना करना पड़ सकता है, बारिश के मौसम में यदि वैकल्पिक रास्ते की स्थिति खराब होती है तो ग्रामीणों के लिए परेशानी और बढ़ सकती है,खासकर आपातकालीन सेवाओं को लेकर प्रशासन की व्यवस्था महत्वपूर्ण होगी,एंबुलेंस को वैकल्पिक मार्ग से अनुमति दी गई है,लेकिन लगातार बारिश की स्थिति में मार्ग की वास्तविक स्थिति पर भी नजर रखना जरूरी होगा।

अब असली चुनौती पुल की मरम्मत

फिलहाल प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से रास्ता बंद कर दिया है,लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कब शुरू होगी और सामान्य आवागमन कब बहाल होगा? यदि पुल की मरम्मत में लंबा समय लगता है तो डायवर्जन का असर भी लंबे समय तक बना रह सकता है। इसलिए संबंधित विभाग को पुल का तकनीकी परीक्षण कराने,क्षति का आकलन करने और आवश्यक मरम्मत अथवा पुनर्निर्माण की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ाने की जरूरत होगी,बारिश के मौसम में पुल-पुलियों की स्थिति लगातार बदल सकती है,ऐसे में केवल एक बार निरीक्षण के बजाय नियमित निगरानी भी जरूरी होगी।

सुरक्षा पहले,लेकिन मरम्मत की रफ्तार भी जरूरी

तरईया नदी का पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद प्रशासन द्वारा आवागमन रोकने का निर्णय फिलहाल लोगों की सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है,लेकिन ग्रामीणों के लिए यह राहत तभी पूरी होगी, जब पुल की मरम्मत अथवा वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था भी जल्द तैयार हो, फिलहाल कोटाडोल-कमर्जी मार्ग बंद है,सफर सात किलोमीटर लंबा हो गया है और प्रशासन ने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के साथ डायवर्जन लागू कर दिया है,अब निगाह इस बात पर रहेगी कि 7 सितंबर तक पुल की स्थिति में कितना सुधार होता है,संबंधित विभाग मरम्मत के लिए क्या कदम उठाता है और कब तक कोटाडोल-कमर्जी मार्ग पर सामान्य आवागमन बहाल हो पाता है।

कबाड़ गोदाम में पुलिस का छापा, एल्यूमिनियम तार से भरी पिकअप जब्त

संतोष जायसवाल की दुकान में हुई कार्रवाई,बिजली सप्लाई में उपयोग होने वाले तार मिले; पूछताछ जारी

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

शहर के एक कबाड़ गोदाम में पुलिस ने छापेमारी कर बिजली सप्लाई में उपयोग होने वाले एल्यूमिनियम तार बरामद किए हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने एक पिकअप वाहन में लोड तार जब्त किया है। मामले में कबाड़ संचालक से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस ने संतोष जायसवाल के कबाड़ गोदाम में दबिश दी। यह गोदाम अमरजीत भगत के फार्म मुड़ने से ठीक पहले पेट्रोल पंप के पास स्थित बताया जा रहा है। छापे के दौरान पुलिस टीम को बड़ी मात्रा में एल्यूमिनियम तार मिले,

जिनका उपयोग बिजली सप्लाई में किया जाता है। पुलिस बरामद तारों के संबंध में जानकारी जुटा रही है कि यह सामग्री कहां से लाई गई थी और इसके दस्तावेज उपलब्ध हैं या नहीं। मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड लगातार दूसरे वर्ष प्रदान करेगा विश्व पर्यटन दिवस पुरस्कार-2026

होटल से टूर ऑपरेटर,होमस्टे,इको-टूरिज्म,एडवेंचर पर्यटन और सोशल मीडिया तक के 10 श्रेणियों में होंगे विश्व पर्यटन दिवस पुरस्कार-2026 प्रत्येक विजेता को 11 हजार रुपए एवं मेमेंटो

-संवाददाता-

एमसीबी,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ में पर्यटन क्षेत्र को नई पहचान देने,पर्यटन से जुड़े उद्यमियों, संस्थाओं एवं व्यक्तियों के उत्कृष्ट कार्यों को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के पर्यटन स्थलों के विकास,संवर्धन एवं प्रचार-प्रसार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड द्वारा विश्व पर्यटन दिवस पुरस्कार-2026 प्रदान किए जाएंगे। इस पुरस्कार योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र में

उल्लेखनीय योगदान देने वाले होटल,पंजीकृत टूर ऑपरेटर,जिले, पर्यटन स्टार्टअप,रिसॉर्ट,पर्यटक सूचना केंद्र,होमस्टे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर,इको-टूरिज्म साइट और एडवेंचर टूरिज्म संचालकों को सम्मानित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत कुल 10 श्रेणियों में एक-एक पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक विजेता को 11 हजार रुपए की पुरस्कार राशि एवं मेमेंटो प्रदान किया जाएगा। पुरस्कार के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। विश्व पर्यटन दिवस पुरस्कार-2026 की खासियत यह है कि इसमें पर्यटन को केवल पर्यटन स्थलों तक सीमित न रखते हुए उससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों को भी सम्मान के दायरे में शामिल किया गया है।

वसुंधरा सिटी मॉल निर्माण स्थल पर मजदूर की करंट से मौत

मटेरियल लिफ्ट ट्रॉली में करंट आने से अशोक श्याम ने अस्पताल में तोड़ा दम,अब जांच का सवाल...सुरक्षा मानकों, अर्थिंग और श्रमिक पंजीयन की जांच करेगा कौन?

-संवाददाता-

अंबिकापुर,31अगस्त 2026 (घटती-घटना)। प्रतीक्षा बस स्टैंड के समीप निर्माणाधीन वसुंधरा सिटी मॉल में सोमवार को हुए दर्दनाक हादसे ने शहर में चल रहे बड़े निर्माण कार्यों में श्रमिकों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्माण स्थल पर मटेरियल लिफ्ट ट्रॉली में अचानक करंट प्रवाहित होने से बेलखेरिखा निवासी अशोक कुमार श्याम इसकी चपेट में आ गए। गंभीर हालत में उन्हें संजीवनी अस्पताल ले जाया गया,जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह महज दुर्घटना थी या सुरक्षा मानकों की अनदेखी का नतीजा? यदि निर्माण स्थल पर विद्युत सुरक्षा,अर्थिंग और श्रमिकों के लिए आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था थी,तो लोहे की ट्रॉली में करंट कैसे दौड़ा?

सामान लोड करते समय ट्रॉली में दौड़ा करंट

जानकारी के अनुसार अशोक कुमार श्याम निर्माणाधीन मॉल में मजदूरी करते थे। सोमवार को वह अन्य दिनों की तरह निर्माण कार्य में लगे थे। बताया जा रहा है कि वह मटेरियल लिफ्ट ट्रॉली में निर्माण सामग्री लोड कर रहे थे। इसी दौरान ट्रॉली में अचानक विद्युत करंट प्रवाहित हो गया और अशोक उसकी चपेट में आ गए। करंट लगने के बाद वह गंभीर रूप से झुलस गए। सहकर्मियों और मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया,लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।

एक मजदूर की मौत,लेकिन जवाबदेही किसकी?

हादसे के बाद अब केवल मुआवजे की बात पर्याप्त नहीं होगी। यह जांच भी जरूरी है कि निर्माण स्थल पर श्रमिकों की सुरक्षा के लिए निर्धारित मानकों का पालन किया जा रहा था या नहीं।

सवाल कई है...

- मटेरियल लिफ्ट ट्रॉली में उचित अर्थिंग और विद्युत सुरक्षा व्यवस्था थी या नहीं?
- विद्युत वायरिंग और उपकरणों का नियमित निरीक्षण किया गया था या नहीं?
- मजदूरों को सेफ्टी शूज, इंसुलेटेड दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए गए थे?
- निर्माण स्थल पर जिम्मेदार सेफ्टी अधिकारी/सुपरवाइजर मौजूद था या नहीं?
- क्या श्रमिक अशोक कुमार श्याम का संबंधित विभाग में पंजीयन था?
- निर्माण स्थल का श्रम एवं विद्युत सुरक्षा विभाग द्वारा आखिरी बार निरीक्षण कब किया गया था?
- क्या निर्माण एजेंसी द्वारा सुरक्षा मानकों का प्रमाणित ऑडिट कराया गया था?

श्रम विभाग की भूमिका पर भी उठे सवाल

शहर में लगातार बड़े व्यावसायिक और बहुमंजिला निर्माण कार्य चल रहे हैं। ऐसे स्थानों पर बड़ी संख्या में मजदूर काम करते हैं। निर्माण कार्य की रफ्तार के साथ यदि श्रमिक सुरक्षा पीछे छूट जाए तो ऐसी घटनाएं किसी भी परिवार को हमेशा के लिए उजाड़ सकती हैं।

अशोक की मौत के बाद यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या संबंधित विभाग केवल कागजों में निरीक्षण करता है या वास्तव में निर्माण स्थलों पर जाकर

सुरक्षा इंतजामों पर गंभीर सवाल...

सुरक्षा व्यवस्था की जांच भी करता है? यदि नियमित निरीक्षण हुआ था तो

मटेरियल लिफ्ट जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था में विद्युत सुरक्षा की कमी पकड़ में क्यों नहीं आई? और यदि निरीक्षण नहीं हुआ था तो इतने बड़े निर्माण स्थल को किस आधार पर काम करने दिया जा रहा था?

मुआवजे से आगे जिम्मेदारी तय करने की जरूरत

परिजनों को नियमानुसार सहायता और मुआवजा मिलना जरूरी है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि हादसे की तकनीकी और प्रशासनिक जांच हो। विद्युत विभाग, श्रम विभाग और संबंधित निर्माण एजेंसी को यह स्पष्ट करना चाहिए कि दुर्घटना का वास्तविक कारण क्या था।

सिर्फ पंचनामा और मुआवजे की प्रक्रिया पूरी कर मामले को बंद कर देना जनहित में पर्याप्त नहीं होगा। यदि जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आती है तो जिम्मेदार व्यक्ति, निर्माण एजेंसी अथवा संबंधित प्रबंधन पर नियमानुसार कार्रवाई भी होनी चाहिए।

आज अशोक गया, कल किसी और परिवार की बारी न हो अशोक कुमार श्याम की मौत केवल एक परिवार की त्रासदी नहीं है, बल्कि शहर में चल रहे निर्माण कार्यों में श्रमिक सुरक्षा को लेकर चेतावनी भी है। बड़े-बड़े मॉल और इमारतें विकास की पहचान हो सकती हैं, लेकिन उनके निर्माण में लगे मजदूरों की जिंदगी की कीमत पर विकास स्वीकार्य नहीं हो सकता। अब प्रशासन से अपेक्षा है कि वह वसुंधरा सिटी मॉल निर्माण स्थल की सुरक्षा व्यवस्था, विद्युत वायरिंग, अर्थिंग, लिफ्ट ट्रॉली, श्रमिक पंजीयन, सुरक्षा उपकरण और पूर्व निरीक्षण रिकॉर्ड की निष्पक्ष जांच कराए और रिपोर्ट सार्वजनिक करे।

ड्राई डे पर क्लब ग्रीन पार्क में शराब परोसने का आरोप

सीसीटीवी जांच की उठी मांग

- 15 अगस्त 2026 के ड्राई डे के दिन शराब परोसने का आरोप
- क्लब में केवल सदस्यों का प्रवेश, सदस्यता रजिस्टर की जांच की मांग
- एमपी की अवैध शराब सप्लाई का भी आरोप
- जिला अधिकारी से कथित संरक्षण मिलने की चर्चा

15 अगस्त को क्लब में कौन-कौन था मौजूद? जांच सदस्यता सूची और प्रवेश रिकॉर्ड्स

एमपी की शराब परोसने और सप्लाई के गंभीर आरोप विभाग के पास है वीडियो साक्ष्य का दावा

अधिकारी से बार-बार मुलाकात पर उठे सवाल सप्ताह में 2-3 बार क्यों हो रही मुलाकात?

ड्राई डे के दिन की निष्पक्ष जांच से ही होगा सच का खुलासा

15 अगस्त के दिन क्लब में कौन-कौन मौजूद था? सदस्यता रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और शराब स्टॉक की जांच से सामने आ सकता है सच

-रवि सिंह-

मनेंद्रगढ़ ,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त 2026 के ड्राई डे के दौरान एनएच-43 स्थित क्लब ग्रीन पार्क में कथित रूप से शराब परोसे जाने और मध्यप्रदेश की शराब उपलब्ध होने के आरोपों ने आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं,सोशल मीडिया पर सामने आई एक स्थानीय पोस्ट में क्लब में ड्राई डे के बावजूद शराब की बिक्री अथवा परोसे जाने का आरोप लगाया गया है,मामला सामने आने के बाद अब शहरवासियों की मांग है कि इसे केवल सोशल मीडिया के आरोप तक सीमित न रखते हुए 15 अगस्त के दिन के सीसीटीवी फुटेज,क्लब के प्रवेश रजिस्टर, सदस्यता रिकॉर्ड और शराब से संबंधित उपलब्ध दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए,इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है,ऐसे में पूरे मामले में जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि ड्राई डे के दौरान वास्तव में शराब परोसी गई थी या नहीं, लेकिन आरोप गंभीर होने के कारण आबकारी विभाग की ओर से तथ्यात्मक जांच की मांग जरूर उठ रही है।

ड्राई डे पर शराब परोसने का आरोप- स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्व पर प्रदेश में शराब की बिक्री और परोसने पर प्रतिबंध रहता है, ऐसे में यदि किसी क्लब या प्रतिष्ठान में प्रतिबंध के बावजूद शराब परोसे जाने की शिकायत सामने आती है तो संबंधित विभाग के लिए उसकी जांच महत्वपूर्ण हो जाती है, क्लब ग्रीन पार्क को लेकर सामने आए आरोप में कहा गया है कि 15 अगस्त के ड्राई डे पर भी क्लब में शराब उपलब्ध कराई गई,यही आरोप अब पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है, यदि उस दिन क्लब में शराब परोसी गई थी तो यह पता लगाना जरूरी होगा कि शराब कहां से आई,किसके माध्यम से पहुंची और किसके निर्देश पर उसे परोसा गया। वहीं यदि ऐसा नहीं हुआ था तो सीसीटीवी और अन्य रिकॉर्ड की जांच के बाद क्लब प्रबंधन भी अपनी स्थिति स्पष्ट कर सकता है।

क्लब में सिर्फ सदस्य आते हैं...तो 15 अगस्त की सूची सामने आए...

प्राप्त जानकारी के अनुसार क्लब ग्रीन पार्क में केवल क्लब के सदस्यों को प्रवेश की अनुमति होने की बात सामने आ रही है, ऐसे में 15 अगस्त के दिन क्लब में मौजूद लोगों की सूची इस जांच में महत्वपूर्ण हो सकती है,जांच में यह देखा जा सकता है कि उस दिन क्लब में कितने लोग पहुंचे,उनमें कितने अधिकृत सदस्य थे और क्या किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश दिया गया,इसके लिए गेट रजिस्टर,सदस्यता रिकॉर्ड,सीसीटीवी फुटेज और उस दिन की बुकिंग अथवा अन्य उपलब्ध प्रविष्टियों का मिलान किया जा सकता है,यदि क्लब में प्रवेश केवल सदस्यों के लिए है तो उस दिन मौजूद प्रत्येक व्यक्ति की पहचान और सदस्यता की जांच करना अपेक्षाकृत आसान होना चाहिए।

मध्यप्रदेश की शराब का भी आरोप...

मामले में एक और गंभीर आरोप मध्यप्रदेश की शराब से जुड़ा है,स्थानीय स्तर पर दावा किया जा रहा है कि कथित रूप से मध्यप्रदेश की शराब न केवल क्लब में परोसी जाती है,बल्कि उसकी सप्लाई भी की जाती है,यह आरोप फिलहाल स्वतंत्र रूप से प्रमाणित नहीं है,लेकिन यदि विभाग के पास इस संबंध में कोई वीडियो,फोटो,बिल,बोतल,बैच नंबर अथवा अन्य साक्ष्य उपलब्ध होते हैं तो उनकी जांच के माध्यम से शराब के स्रोत का पता लगाया जा सकता है, विशेष रूप से शराब की बोतलों पर अंकित लेबल,बैच नंबर और निर्माता संबंधी जानकारी की जांच यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि शराब किस राज्य अथवा लाइसेंस प्राप्त स्रोत से आई थी।

सिर्फ वीडियो नहीं,पूरा रिकॉर्ड जांचे

विभाग- आबकारी विभाग के संबंधित अधिकारी नितिन कुमार शुक्ला से जानकारी लेने का प्रयास किया गया,उनके अनुसार मध्यप्रदेश की अवैध शराब की बिक्री से संबंधित वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होने की बात कही गई है और वीडियो उपलब्ध कराने पर उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी,लेकिन मामले में सवाल यह उठ रहा है कि जांच को केवल किसी एक वीडियो तक सीमित रखने के बजाय 15 अगस्त के पूरे घटनाक्रम की जांच क्यों न की जाए? क्योंकि यदि आरोप ड्राई डे पर शराब परोसे जाने का है तो सीसीटीवी फुटेज इस मामले में महत्वपूर्ण साक्ष्य हो सकता है, फुटेज से यह देखा जा सकता है कि उस दिन क्लब के भीतर गतिविधियां क्या थीं, इसके साथ प्रवेश रजिस्टर और सदस्यता रिकॉर्ड का मिलान करने पर यह भी पता लगाया जा सकता है कि क्लब में मौजूद लोग अधिकृत सदस्य थे या नहीं।

सीसीटीवी फुटेज सबसे अहम कड़ी...

इस पूरे मामले में सीसीटीवी जांच को सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है,यदि क्लब परिसर में कैमरे लगे हैं तो 15 अगस्त के पूरे दिन और रात की रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जानी चाहिए, जांच के दौरान प्रवेश और निकास द्वार के अलावा उन स्थानों की रिकॉर्डिंग भी देखी जा सकती है जहां कथित रूप से शराब परोसी जाती है,सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के साथ यदि उस दिन का बिलिंग रिकॉर्ड,स्टॉक रजिस्टर या अन्य उपलब्ध दस्तावेज मिलाए जाएं तो आरोपों की वास्तविकता जांचने में मदद मिल सकती है।

अधिकारी से कथित मुलाकातों पर भी उठे सवाल- मामले में एक सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि क्लब संचालित करने वाला व्यक्ति आबकारी विभाग के कार्यालय में नवीन कुमार शुक्ला से सप्ताह में दो से तीन बार मिलने क्यों आता है और कथित रूप से घंटों मुलाकात करता है,हालांकि किसी अधिकारी से किसी व्यक्ति की मुलाकात मात्र अपने आप में किसी अनियमितता अथवा संरक्षण का प्रमाण नहीं है,सरकारी कार्यालयों में व्यवसायिक और प्रशासनिक कारणों से मुलाकातें होना सामान्य बात हो सकती हैं,लेकिन यदि इन मुलाकातों को लेकर संरक्षण का आरोप लगाया जा रहा है तो इसकी पुष्टि केवल रिकॉर्ड,शिकायतों और संबंधित अधिकारियों के पक्ष से ही हो सकती है,इसलिए इस आरोप को भी तथ्य के रूप में नहीं, बल्कि जांच की मांग के रूप में देखा जाना चाहिए।

संरक्षण के आरोपों की भी हो निष्पक्ष जांच- स्थानीय स्तर पर संबंधित जिला अधिकारी से कथित संरक्षण मिलने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं, यह आरोप गंभीर है,लेकिन फिलहाल इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, यदि किसी अधिकारी पर संरक्षण देने का आरोप है तो जांच एजेंसी को यह देखना होगा कि संबंधित अधिकारी के कार्यकाल में क्लब के खिलाफ कोई शिकायत आई थी या नहीं,उस पर क्या कार्रवाई हुई,निरीक्षण कब-कब किया गया और क्या किसी उल्लंघन के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई,इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि विभागीय निगरानी नियमित थी या नहीं।

हर सप्ताह सीसीटीवी जांच का सुझाव- शहरवासियों की मांग है कि क्लब ग्रीन पार्क जैसे प्रतिष्ठानों की निगरानी केवल किसी विवाद के बाद न हो,बल्कि नियमित व्यवस्था बनाई जाए,इसके तहत आबकारी विभाग के अधिकारियों द्वारा क्लब के सीसीटीवी और संबंधित रिकॉर्ड की नियमित जांच एवं निरीक्षण रिपोर्ट तैयार किए जाने का सुझाव दिया जा रहा है,यदि प्रत्येक निरीक्षण का रिकॉर्ड मौजूद रहे तो भविष्य में किसी शिकायत के सामने आने पर विभाग के पास यह बताने के लिए तथ्य होंगे कि किस तारीख को क्या जांच की गई थी और क्या पाया गया था।

अब जांच से ही साफ होगी तस्वीर- क्लब ग्रीन पार्क को लेकर सामने आए आरोपों का अंतिम निष्कर्ष जांच के बाद ही निकाला जा सकता है। क्लब प्रबंधन का पक्ष भी इस मामले में महत्वपूर्ण होगा,यदि आरोप गलत हैं तो सीसीटीवी,सदस्यता रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज उनकी स्थिति स्पष्ट कर सकते हैं,वहीं यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सवाल उठेगा कि ड्राई डे के दिन शराब क्लब तक कैसे पहुंची और विभागीय निगरानी के बावजूद उसे कैसे परोसा गया? फिलहाल सबसे जरूरी कदम यही है कि 15 अगस्त 2026 के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर उनकी जांच कराई जाए,क्लब में मौजूद लोगों की सदस्यता सत्यापित की जाए और उस दिन के शराब संबंधी रिकॉर्ड का मिलान किया जाए,क्योंकि इस मामले में सोशल मीडिया की चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण अब सीसीटीवी,रजिस्टर और सरकारी रिकॉर्ड हैं,यदि विभाग निष्पक्ष जांच करता है तो कुछ ही दस्तावेज यह तय कर सकते हैं कि मामला महज आरोप था या ड्राई डे के दिन नियमों को दरकिनार कर वास्तव में शराब परोसी गई थी।

30 गोवंश तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार आरोपी गिरफ्तार,जेल भेजा

डिंडो चौकी पुलिस की कार्रवाई...16 जुलाई को 30 गोवंश को क्रूरतापूर्वक बांधकर ले जाने का था आरोप...

-संवाददाता-

डिंडो/बलरामपुर,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

डिंडो चौकी पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपी की पहचान इब्राहिम सिद्दीकी उर्फ डाबर (निवासी बीरेन्द्रनगर) के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज था।

16 जुलाई को 30 गोवंश के साथ मिला था मामला

पुलिस के मुताबिक 16 जुलाई 2026 को बसंतपुर निवासी आशुतोष कुमार गुप्ता को सूचना मिली थी कि ग्राम बीरेन्द्रनगर स्थित क्रेशर के पास बड़ी संख्या में गाय,बैल और बछियों को रस्सियों से बांधकर ले जाने की तैयारी की जा रही है। सूचना के बाद ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचने पर करीब 30 रास गोवंश मिले। आरोप है कि इब्राहिम सिद्दीकी अपने दो अन्य साथियों के साथ गोवंश को ले जाने की तैयारी में था। ग्रामीणों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए। मामले में शिकायत के आधार पर डिंडो चौकी में अपराध क्रमांक 54/2026 दर्ज कर जांच शुरू की गई। पुलिस ने छत्तीसगढ़ पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत कार्रवाई की।

डेढ़ महीने से चल रही थी तलाश

घटना के बाद से आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर था। पुलिस लगातार उसके संभावित ठिकानों पर तलाश कर रही थी। इसी दौरान 31 अगस्त 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने घेराबंदी कर इब्राहिम सिद्दीकी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया,जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

उत्तर छत्तीसगढ़ में बदलेगा मौसम का मिजाज,भारी बारिश का अलर्ट...

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र का असर,बीते को अत्यधिक बारिश की संभावना थी,कोरिया-एमसीबी में प्रशासन अलर्ट

-संवाददाता-

कोरिया,31 अगस्त 2026 (घटती-घटना)।

बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है,भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 30 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है,वहीं 31 अगस्त को अत्यधिक भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए उत्तर छत्तीसगढ़ के जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की जरूरत बताई गई थी। बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिमी हिस्से तथा पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा तट से लगे क्षेत्र में बना सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र अब मौसम को प्रभावित कर रहा है,इसके चलते पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। इसका असर छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों में भी देखने को मिल सकता है।

बीते दिवस को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी...

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 31 अगस्त का दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है,इस दौरान छत्तीसगढ़ में कहीं-कहीं अत्यधिक भारी बारिश की स्थिति बन सकती है। लगातार और तेज बारिश होने की स्थिति में निचले इलाकों में जलभराव,नदी-नालों के जलस्तर में वृद्धि तथा ग्रामीण और संपर्क मार्गों पर आवागमन प्रभावित होने की आशंका बनी रहेगी,खासकर नदी-नालों के आसपास रहने वाले लोगों को मौसम की स्थिति पर नजर रखने की जरूरत होगी,बारिश के दौरान जलस्तर अचानक बढ़ने की स्थिति में छोटी पुल-पुलियों और रपटों से गुजरना जोखिमपूर्ण हो सकता है।

कोरिया और बैकुंठपुर में बढ़ी चिंता- उत्तर छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले और बैकुंठपुर क्षेत्र में भी मौसम को लेकर विशेष सतर्कता जरूरी है,जिले के कई ग्रामीण इलाकों में सड़कें,पुल-पुलियां और कच्चे संपर्क मार्ग बारिश के दौरान प्रभावित होते हैं,ऐसे में भारी बारिश की स्थिति बनने पर ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की समस्या बढ़ सकती है जिला प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए भी आने वाले दिनों में चुनौती बढ़ सकती है,लगातार बारिश के कारण जलभराव,पेड़ गिरने,बिजली आपूर्ति प्रभावित होने अथवा सड़क मार्ग बाधित होने जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां रखना जरूरी होगा।

नदी-नालों से दूरी बनाए रखने की अपील-

बारिश के दौरान प्रशासन की ओर से लोगों को नदी, नाले और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की सलाह दी गई है,विशेष रूप से बच्चों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को ऐसे स्थानों पर जाने से बचना चाहिए जहां पानी का बहाव तेज हो,बारिश के दौरान सामान्य दिखाई देने वाला पुल या रपटा भी अचानक खतरनाक हो सकता है,पानी का बहाव बढ़ने पर सड़क के ऊपर से पानी गुजरने की स्थिति में वाहन लेकर पार करने का प्रयास दुर्घटना का कारण बन सकता है,इसलिए मौसम खराब होने की स्थिति में जरूरी नहीं होने पर यात्रा टालना और प्रशासन द्वारा जारी स्थानीय चेतावनियों का पालन करना सुरक्षित विकल्प होगा।

कच्चे रास्तों और पुल-पुलियों पर भी नजर-

ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश का सबसे तत्काल असर कच्चे रास्तों और छोटे पुल-पुलियों पर दिखाई देता है, मिट्टी धंसने,सड़क कटने या पुलिया के ऊपर पानी आने से कई गांवों का संपर्क अस्थायी रूप से प्रभावित हो सकता है,ऐसी स्थिति में स्थानीय प्रशासन को संवेदनशील मार्गों की निगरानी बढ़ानी होगी,ग्रामीणों से भी अपील की गई है कि किसी मार्ग पर पानी का तेज बहाव दिखाई देने पर जोखिम लेकर उसे पार न करें।

प्रायद्वीपीय भारत में कमजोर रहेगा मानसून...

मौसम विभाग के अनुसार जहां बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र के कारण पूर्वी और मध्य भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है,वहीं प्रायद्वीपीय भारत में आगामी एक सप्ताह के दौरान मानसूनी गतिविधियां अपेक्षाकृत कमजोर रह सकती हैं,यानी देश के अलग-अलग हिस्सों में मानसून का प्रभाव एक जैसा नहीं रहेगा, छत्तीसगढ़ में अगले कुछ दिनों में बारिश की गतिविधि बढ़ने की संभावना इसी मौसम प्रणाली से जुड़ी हुई है।

प्रशासन के साथ आम लोगों को भी रहना होगा सतर्क

मौसम विभाग की चेतावनी के बीच अब प्रशासन के साथ आम लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, तेज बारिश के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचना,नदी-नालों से दूरी रखना और स्थानीय प्रशासन की चेतावनियों का पालन करना जरूरी होगा,31 अगस्त को अत्यधिक बारिश की संभावना के मद्देनजर कोरिया, बैकुंठपुर और उत्तर छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों में विशेष सतर्कता जरूरी था,मौसम की स्थिति तेजी से बदल सकती है,इसलिए नागरिकों को आधिकारिक मौसम बुलेटिन और स्थानीय प्रशासन की सूचनाओं पर नजर बनाए रखनी चाहिए,फिलहाल बंगाल की खाड़ी का निम्न दबाव क्षेत्र छत्तीसगढ़ के लिए बारिश लेकर आता दिखाई दे रहा है,अब देखना होगा कि 31 अगस्त की बारिश कितनी व्यापक रही और इसका असर उत्तर छत्तीसगढ़ के नदी-नालों,ग्रामीण मार्गों और जनजीवन पर कितना पड़ा है।

करीना कपूर की दायरा का दमदार ट्रेलर रिलीज

कानून और न्याय की लड़ाई में पृथ्वीराज से होगा आमना-सामना

दायरा का ट्रेलर करीना कपूर खान और पृथ्वीराज सुकुमारन के बीच एक तनावपूर्ण टकराव को दिखाता है। वे दोनों पुलिस ऑफिसर हैं जो नाबालिगों से जुड़े अपराध के एक मामले में आमने-सामने आ जाते हैं।मेघना गुलजार की डायरेक्ट की गई यह थ्रिलर फिल्म कानून,न्याय और जवाबदेही के बीच के टकराव को दिखाती है,क्योंकि इसमें एक विवादित पुलिस एनकाउंटर की जांच आगे बढ़ती है।

किस बारे में है दायरा?

करीना कपूर खान ने डीसीपी अजूनी कोहली का किरदार निभाया है,जबकि पृथ्वीराज सुकुमारन ने डीसीपी रमन कुमार का रोल किया है। ट्रेलर की शुरुआत एक पुलिस एनकाउंटर से जुड़े मामले पर दोनों अधिकारियों के अलग-अलग रुख से होती है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ती है,ड्यूटी और

न्याय को लेकर उनके नजरिए में टकराव होने लगता है।

मामला तब और गंभीर हो जाता है जब एक परिवार अपनी लापता बेटी को खोजने में मदद के लिए अधिकारियों से संपर्क करता है। जांच के दौरान, एक ऐसे आरोपी के बारे में जानकारी सामने आती है जो कथित तौर पर पिछले दो सालों से उसी रास्ते पर सक्रिय था।

क्या है ट्रेलर में?

ट्रेलर नाबालिग अपराधियों से जुड़े कानूनी ढांचे पर भी सवाल उठाता है। एक मुख्य बहस यह है कि क्या रेप और हत्या जैसे गंभीर अपराधों के आरोपी नाबालिगों के मामलों में नाबालिगों की सुरक्षा से जुड़े कानून लागू होने चाहिए।

दोनों अधिकारियों के बीच असहमति सिर्फ उस खास मामले तक ही सीमित नहीं है। वे एक-दूसरे की प्रक्रिया, जवाबदेही और पुलिस अधिकारी के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों की सीमाओं को समझने के तरीके पर सवाल उठाते हैं।

कब रिलीज होगी दायरा?

यश केसवानी,सीमा अग्रवाल और मेघना गुलजार द्वारा लिखी गई दायरा सच्ची घटनाओं पर आधारित है। यह फिल्म दिखाती है कि कैसे एक बड़े अपराध से जनता में आक्रोश पैदा होता है और कई जांच प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं।

ट्रेलर में जितेंद्र जोशी,क्षिति जोग,कंवलजीत सिंह,संदीप कुलकर्णी और तृप्ति खामकर भी सहायक भूमिकाओं में हैं। मेघना गुलजार के निर्देशन में बनी यह फिल्म 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

बिग बॉस के साउथ प्रीमियर से पहले बड़ा सरप्राइज

नागार्जुन से लेकर मोहनलाल तक,एक प्रोमो में दिखे 4 सुपरस्टार्स

नागार्जुन अक्किनेनी,मोहनलाल,विजय सेतुपति और किच्चा सुदीपा साउथ के बिग बॉस के प्रीमियर से पहले एक खास प्रोमो के लिए एक साथ आए। मेकर्स ने नया प्रोमो शेयर किया है,जिसमें चारों सुपरस्टार ने बताया कि 6 सितंबर को तमिल,तेलुगु,कन्नड़ और मलयालम भाषा में शो टेलीकास्ट होगा। बिग बॉस फैंस के लिए अच्छी खबर है,क्योंकि यह रियलिटी शो तेलुगु,मलयालम,तमिल और कन्नड़ भाषा के नए सीजन के साथ एक बार फिर टीवी पर दस्तक देने के लिए तैयार है। अब एक बड़े क्रॉसओवर प्रोमो में चारों होस्ट नागार्जुन अक्किनेनी,मोहनलाल,विजय सेतुपति और किच्चा सुदीपा एक साथ नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर साउथ के बिग बॉस का यह प्रोमो तेजी से वायरल हो रहा है, जो शो के ग्रैंड प्रीमियर से पहले शेयर किया गया है। ये शो चार अलग-अलग भाषा में 6 सितंबर 2026 को शुरू होंगे।

बिग बॉस प्रोमो में दिखे 4 सुपरस्टार्स

1 मिनट 33 सेकंड के इस प्रोमो में रियलिटी शो के तमिल,तेलुगु,कन्नड़ और मलयालम वर्जन को होस्ट करने वाले चारों सुपरस्टार्स होस्ट एक साथ मजेदार अंदाज में खाने-पीने का मजा लेते और अलग-अलग कल्चर को आजमाते हुए दिख रहे हैं। नागार्जुन अक्किनेनी तेलुगु और मोहनलाल मलयालम वर्जन को होस्ट करेंगे,जबकि विजय सेतुपति तमिल और किच्चा सुदीपा एक बार फिर कन्नड़ वर्जन के साथ लौट रहे हैं।

ओटीटी पर कहां देखें साउथ का बिग बॉस

इस प्रोमो में चारों रीजनल वर्जन को जोड़ने के लिए होस्ट के राज्यों के खाने-पीने की चीजों का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही उनकी अलग-अलग सांस्कृतिक पहचान को भी बनाए रखा गया है।, जहां बिग बॉस तमिल और बिग बॉस तेलुगु का यह 10वां सीजन है। वहीं मोहनलाल शो की शुरुआत से अब तक 8वीं बार होस्ट के तौर पर वापसी कर रहे हैं। इसके अलावा,बिग बॉस कन्नड़ का यह 13वां साल है। तमिल वर्जन विजय टीवी पर दिखाया जाएगा,जबकि तेलुगु वर्जन स्टार मां पर उपलब्ध होगा। साथ ही मलयालम शो एशियानेट पर और कन्नड़ वर्जन कलर्स कन्नड़ पर प्रसारित होगा। इसके अलावा, शो की 24×7 स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी उपलब्ध होगी।

बिग बॉस 20 कब होगा शुरू

बिग बॉस के सभी साउथ वर्जन 6 सितंबर को एक साथ शुरू होंगे। ये चारों शो एक ही लॉन्च इवेंट का हिस्सा होंगे,लेकिन इनकी अपनी-अपनी भाषाएं,कंटेस्टेंट और कहानियां होंगी। दिलचस्प बात यह है कि सलमान खान द्वारा होस्ट किया जाने वाला बिग बॉस 20 भी 6 सितंबर को शुरू होने वाला है। यह होस्ट के तौर पर एक्टर का लगातार 17वां साल भी होगा।

चिरंजीवी का बड़ा खुलासा : जूही चावला को लेकर मन में आई थी ये बात...

मेगास्टार चिरंजीवी ने एक बार माना था कि उन्हें 1990 की फिल्म प्रतिबंध में जूही चावला के रोल के लिए उनके सही होने पर शक था। मीडिया के साथ एक पुरानी बातचीत में, चिरंजीवी ने बताया कि उन्होंने जूही को फिल्म कयामत से कयामत तक में देखा था, जिसमें वह एक चुलबुली युवा लड़की के तौर पर दिखी थीं। इसलिए,उन्हें पक्का नहीं था कि जूही प्रतिबंध में शांति के रोल के लिए पूरी तरह सही रहेंगी या नहीं। हालांकि,जब उन्होंने उस लुक में उनकी तस्वीर देखी,तो उन्होंने उन्हें मौका देने का फैसला किया। चिरंजीवी ने बताया कि जूही का चेहरा मासूम था,जैसा कि इस रोल के लिए ज़रूरी था। फिल्म में जूही के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए चिरंजीवी ने कहा,मैंने कयामत से कयामत तक देखी थी,जिसमें वह एक टीनएज लड़की और बहुत चुलबुले किरदार में थीं। इसलिए,हमें शक था कि वह इस किरदार के लिए सही रहेंगी या नहीं। एक बार हमने उनकी तस्वीर देखी जो हमारे गेटअप से मिलती-जुलती थी। तब हमने सोचा कि यह अच्छा रहेगा,बिल्कुल, हम उन्हें कास्ट क्यों नहीं कर सकते। और उनका चेहरा भी वैसा ही मासूम था,इसलिए हमने जूही को आज़माया। वह बहुत अच्छी थीं,और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। चिरंजीवी ने फिल्म में जूही की परफॉर्मेंस की भी तारीफ़ की और कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक खास सीन का ज़िक्र करते हुए,मेगास्टार ने कहा,और मुझे लगता है कि हम उनकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हैं,खासकर कोर्ट वाले सीन से। वह जेल वाला सीन,जेल के पास,जब मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा होता हूँ। और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रवि राजा पिनिसेट्टी के डायरेक्शन में बनी प्रतिबंध में रामी रेड्डी ने भी अहम रोल निभाया था।

सिनेमाघरों में दिखेगा मिर्जापुर: द मूवी का खौफ

सेंसर बोर्ड की कसौटी तो हुई पार, लेकिन इंटीमेट सीन पर चली कैंची

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर तहलका मचाने के बाद सुपरहिट फ्रेंचाइजी मिर्जापुर अब सिनेमाघरों में बड़ा धमाका करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अपनी रिलीज से महज कुछ दिन पहले मिर्जापुरः द मूवी ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की प्रक्रिया को पार कर लिया है। मेकर्स के लिए राहत की बात यह है कि सेंसर बोर्ड ने इस बहुचर्चित फिल्म को बिना किसी बड़े बड़े कट के पास कर दिया है, जिससे दर्शक इसके मूल और अनफिल्टर्ड अनुभव का बड़े पर्दे पर लुत्फ उठा सकेंगे।

ए प्रमाण पत्र के साथ पास हुई फिल्म, 3 घंटे 17 मिनट की होगी अवधि

सेंसर बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने गहन समीक्षा के बाद फिल्म को ए (18 साल से ज्यादा) प्रमाण पत्र दिया है। फिल्म की कुल अवधि 197 मिनट यानी 3 घंटे और 17 मिनट तय की गई है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि फिल्म से कई सीन काटे गए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मेकर्स को अपनी मुख्य कहानी में कोई बड़ा कट नहीं लगाना पड़ा है। सेंसर बोर्ड ने केवल कुछ संवादों और दृश्यों में मामूली मॉडिफिकेशन के निर्देश दिए हैं ताकि सिनेमाघरों के माहौल के अनुसार फिल्म को संतुलित रखा जा सके।

गालियों पर चली सेंसर की कैंची, इंटीमेट सीन्स पर 50 फीसदी की कटौती

फिल्म को पास करते समय सीबीएफसी ने कुछ बदलावों के आदेश दिए हैं। चार जगहों पर अपशब्दों को म्यूट किया गया है, जबकि छह स्थानों पर आपत्तिजनक शब्दों को बदला गया है। संवादों के स्तर पर गले से लग गर जैसे वाक्यांश में बदलाव कराए गए। इसके अलावा फिल्म के पहले हिस्से में एक शब्द को कमर से बदला गया तो दूसरे हिस्से में लंठ शब्द को हटाया गया, देसी बोलचाल में जिसका मतलब बेवकूफ होता हैष इसके साथ ही जाति से जुड़े एक संदर्भ को भी बदलने के निर्देश दिए गए हैं। सीन मॉडिफिकेशन की बात करें तो बोर्ड ने इंटीमेट और संवेदनशील दृश्यों के असर को दृश्य और ऑडियो दोनों स्तरों पर 50 प्रतिशत तक कम करने को कहा है। ये बदलाव इंटरवल से पहले और बाद के दो अलग-अलग सीन्स में किए गए हैं, जिससे लगभग 35 सेकंड के इंटीमेट कंटेंट पर कैंची चली है। दिलचस्प बात यह है कि सीबीएफसी ने फिल्म के हिंसक या खूनी दृश्यों में कोई कटौती नहीं की है, जिससे सीरीज का वास्तविक डार्क और थ्रिलर टोन बरकरार रहेगा।

अकेले देखने वाली सीरीज अब बनेगी ग्रूप पार्टी : पंकज त्रिपाठी

फिल्म के बड़े पर्दे पर आने को लेकर कालीन भैया का किरदार निभाने वाले पंकज त्रिपाठी बेहद उत्साहित हैं। उन्होंने थिएटर के अनुभव पर बात करते हुए कहा कि जब कोई कला रूप किसी समूह या समुदाय के साथ देखा जाता है, तो उसका असर पूरी तरह बदल जाता है। पहले जहां मिर्जापुर अकेले में देखी जाने वाली सीरीज थी, वहीं अब यह सामूहिक रूप से सिनेमाघरों में पार्टी मोड का मजा देगी। दुनिया और किरदार वही रहेंगे,लेकिन कहानी नई होगी और इसका कैनवास काफी विशाल होगा।

4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी मिर्जापुर

गुरमीत सिंह के निर्देशन और पुनीत कृष्णा द्वारा लिखित इस फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर की एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित किया गया है। अमेजॉन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत यह थ्रिलर फिल्म 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। फिल्म में पंकज त्रिपाठी (कालीन भैया),अली फजल (गुड्डू पंडित),दिव्येंदु (मुन्ना भैया),रसिका दुगल (बीना त्रिपाठी),श्वेता त्रिपाठी शर्मा (गोलू गुप्ता),श्रिया पिलगांवकर,जितेंद्र कुमार,रवि किशन और अभिषेक बनर्जी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे।

जाह्नवी कपूर ने समर को कहा बाय-बाय

एक्ट्रेस जान्हवी कपूर ने सोशल मीडिया पर एक प्यारे से नोट के साथ गर्मी के मौसम को अलविदा कहा है। अपनी गर्मी की यादों की झलकियां शेयर करते हुए,मिली एक्ट्रेस ने इस मौसम को प्यार से याद किया। इंस्टाग्राम पर जान्हवी ने अपनी गर्मी की तस्वीरों और पलों की एक सीरीज़ पोस्ट की और उन्हें कैप्शन दिया, अलविदा गर्मी,तुम बहुत अच्छी थीं। इस पोस्ट में एक्ट्रेस की गर्मी की डायरी की एक झलक दिखाई गई,क्योंकि उन्होंने इस मौसम को अलविदा कहा। फोटोज़ के इस कलेक्शन में जान्हवी कपूर की शानदार सोलो तस्वीरें हैं,साथ ही उनके दोस्तों के साथ कैंडिड पल भी हैं। एक्ट्रेस ने अपने मेकअप सेशन और बिहाइंड-द-सीन्स पलों की झलकियां भी शेयर कीं, जिससे उनकी गर्मी की यादों की एक झलक मिलती है। कुछ दिन पहले,जान्हवी ने पेरिस से एक वीडियो भी शेयर किया था,जिससे फैंस को शहर में उनके समय की एक झलक मिली। इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, पेरिस में 7 घंटे लेकिन मेरी फ्रेंच गर्ल लिपस्टिक और ऑन द वाइब्स एंड वीडियोज़ के ब्लश के बिना नहीं।जान्हवी कपूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और रेगुलर अपने फोटोशूट,ट्रैवल,फैमिली टाइम और कैंडिड मोमेंट्स की झलकियां शेयर करती रहती हैं, जिससे उनके फैन बेस को उनकी लाइफ के बारे में अपडेटेड रहता है।

प्रोफेशनल फ्रंट पर,जान्हवी कपूर को आखिरी बार शशांक खेतान की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में देखा गया था,जिसमें वरुण धवन,सान्या मल्होत्रा,रोहित सराफ,मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय भी थे। उन्होंने 2018 में धड़क से एक्टिंग में डेब्यू किया और तब से गुंजन सक्सेना :द कारगिल गर्ल,रूही,गुड लक जेरी,मिली,मिस्टर एंड मिसेज माही,उलझन और देवरा : पार्ट 1 जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। जान्हवी को राम चरण के साथ पेद्दी में भी देखा गया था। बुची बाबू सना द्वारा डायरेक्टेड,इस स्पोर्ट्स एक्शन-ड्रामा में राम चरण ने एक क्रॉसओवर एथलीट की भूमिका निभाई, जिसने तीन मुश्किल स्पोर्ट्स–क्रिकेट,रेसलिंग और स्प्रिंटिंग–को चुना।

खेल समाचार

अफगानिस्तान सीरीज में दिखेगा नया चेहरा,टीम इंडिया में एंट्री की तैयारी

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। भारतीय क्रिकेट टीम में नए खिलाड़ियों की एंट्री और पुराने सितारों की वापसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आने वाले समय में टीम इंडिया को कई महत्वपूर्ण सीरीज खेलनी हैं,ऐसे में चयनकर्ताओं की नजर लगातार खिलाड़ियों के प्रदर्शन और फिटनेस पर बनी हुई है। इसी बीच एक ऑलराउंडर को लेकर बड़ी चर्चा शुरू हो गई है,जो करीब पांच साल बाद दोबारा भारतीय टीम में वापसी कर सकता है। टीम इंडिया के लिए ऑलराउंडर हमेशा से अहम भूमिका निभाते रहे हैं। कपिल देव,युवराज सिंह,रविंद्र जडेजा और हार्दिक पंड्या जैसे खिलाड़ियों ने बल्ले और गेंद दोनों से टीम को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई हैं। ऐसे में भारतीय टीम को भविष्य के लिए एक मजबूत ऑलराउंडर विकल्प की तलाश रहती है। इसी कड़ी में एक खिलाड़ी के प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा है।

टूर चैंपियनशिप में होवलैंड ने बढ़त बनाई

अटलांटा,31 अगस्त 2026। अक्षय भाटिया ने बैक नाइन के आखिर में तीन में से दो बोगी कीं और टूर चैंपियनशिप के तीसरे राउंड के बाद 29 खिलाड़ियों में संयुक्त रूप से 22वें स्थान पर आ गए। दूसरे राउंड के बाद टी-11 पर रहने वाले भाटिया ने 1-ओवर 71 का स्कोर किया, जिससे 65-69 और 71 के राउंड के बाद उनका कुल स्कोर 5-अंडर हो गया। भाटिया ने पांचवें होल पर एक शॉट गंवाया, जिसे उन्होंने 12वें होल पर वापस हासिल कर लिया ।

टीम इंडिया सितंबर में खेलेगी 3 टी 20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज

नई दिल्ली,31 अगस्त 2026। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इसका पहला मैच 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। माना जा रहा है कि तीन सितंबर को टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया जाएगा।

टीम इंडिया अब जल्द ही फिर से क्रिकेट के मैदान में नजर आएगी। हाल ही में भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज का समापन हुआ है,जिसे भारतीय टीम ने अपने नाम किया था। हालांकि अब टेस्ट तो दूर हैं, लेकिन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलते हुए भारतीय टीम नजर आएगी। जल्द ही तीन टी20 मैचों की सीरीज होगी,इसके लिए टीम के स्क्वाड का भी ऐलान किया जाना है।

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन टी20 मैचों सीरीज खेली जाएगी

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन टी20 मैचों की सीरीज सितंबर में ही खेली जाएगी। ये सीरीज अहम होगी, क्योंकि इसी के बाद भारतीय टीम एशियन गेम्स के लिए चली जाएगी। एक तरह से देखें तो ये सीरीज तैयारी के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। हालांकि खास बात ये है कि मैच भले ही भारत में खेले जाने हों, लेकिन इसकी मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी एसीबी करेगा। पहला मैच 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। बाकी मैच भी इसी स्टेडियम पर खेले जाएंगे। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बीच माना जा रहा है कि 3 सितंबर यानी सीरीज से दस दिन पहले गुरुवार को टीम का ऐलान किया जा सकता है। अफगानिस्तान अपने प्लेयर्स की लिस्ट पहले ही जारी कर दी है।

श्रेयस अय्यर करते नजर आएंगे भारतीय टीम कप्तानी

टीम का ऐलान चाहे जब हो,लेकिन ये करीब करीब पक्का है कि श्रेयस अय्यर एक बार फिर से भारतीय टीम की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। हालांकि बाकी टीम कैसी होगी,इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। बीसीसीआई की सेलेक्शन कमेटी सभी प्लेयर्स की नजर रखे हुए हैं। जो खिलाड़ी अच्छा खेल दिखा रहे हैं और फिट भी हैं,उन्हें मौका मिलने की पूरी संभावना है।

बहुत अच्छे नहीं हैं श्रेयस के कप्तानी आंकड़े

श्रेयस अय्यर हाल ही में भारतीय टीम के टी20 कप्तान बने हैं, लेकिन उनका आगाज अच्छा नहीं रहा है। हालांकि लगता है कि वे धीरे धीरे लय पकड़ रहे हैं। आगामी अफगानिस्तान सीरीज उनके लिए बतौर कप्तान काफी खास होने वाली है। सीरीज का पहला मैच जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि 13 सितंबर को है। इसके बाद दूसरा मैच 15 और तीसरा 17 सितंबर को खेला जाएगा।

भारत-बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज पर आया नया अपडेट

ढाका,31 अगस्त 2026। इस साल अगस्त-सितंबर में भारतीय टीम को बांग्लादेश का दौरा करना था। लेकिन अब ये दौरा तय समय पर नहीं हो पाएगा। भारत बांग्लादेश सीरीज पर अब तमीम इकबाल ने एक नया अपडेट दिया है। भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली क्रिकेट सीरीज को लेकर एक नया अपडेट आया है,जिसकी जानकारी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष तमीम इकबाल ने दी है। दोनों देशों के बीच वनडे और टी-20 मैचों की यह सीरीज इसी साल अगस्त-सितंबर में खेली जानी थी, लेकिन राजनीतिक माहौल और तनाव की वजह से इस पर अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं। हालांकि,तमीम इकबाल ने यह साफ कर दिया है कि सीरीज को पूरी तरह रद्द नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि मैच होने की उम्मीद अभी भी पूरी तरह बनी हुई है। इससे पहले भी तमीम इकबाल ने इस सीरीज को लेकर बयान जारी किया था।

बांग्लादेश को भारत के खिलाफ 3 वनडे और 3 टी-20 मैचों की सीरीज की मेजबानी करनी है। इस पर बात करते हुए तमीम इकबाल ने कहा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और भारतीय क्रिकेट बोर्ड दोनों ही इस सीरीज को कराने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने बताया कि दोनों बोर्ड मिलकर अब इसके लिए किसी नए समय (विंडो) की तलाश कर रहे हैं। तमीम के इस बयान से यह बात साफ हो गई है कि यह सीरीज अपने तय समय यानी अगस्त-सितंबर में आयोजित नहीं होगी,बल्कि इसे आगे के लिए टाल दिया गया है।

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर, जिला सूरजपुर (छ0ग0)

रा0प्र0क्र0-/अ-20(1)/25-26

ईश्तहार

आगामी तिथि 16/9/2026

इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता / संस्था / विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक आमना खातून पति शाविरूल हक निवासी वार्ड क्र 05 मस्जिद पारा सूरजपुर,थाना व तहसील सूरजपुर, जिला- सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लाट नम्बर 1979/4 रकबा क्रमशः 3161 वर्गफीट भूमि का लीज दिनांक 31/03/2026 को समाप्त होने से आगामी 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था / विभाग को कोई दावा / आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक / लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा / आपत्ति दिनांक 16/9/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

आज दिनांक 13/8/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,सूरजपुर

छत्तीसगढ़ के 5 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स की हो रही नीलामी, मुख्यमंत्री ने निवेशकों से किया सक्रिय भागीदारी का आह्वान

खनिज उत्पादन तक सीमित नहीं रहेगा छत्तीसगढ़,अन्वेषण से एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तक विकसित होगी पूरी वैल्यू चेन : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर,31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ में उपलब्ध समृद्ध खनिज संपदा और क्रिटिकल मिनरल्स की व्यापक संभावनाएं प्रदेश को विकास के नए क्षितिज पर ले जाने की क्षमता रखती हैं। हमारा लक्ष्य केवल धरती से खनिज निकालना नहीं, बल्कि अन्वेषण से उत्खनन, प्रसंस्करण से मूल्य संवर्धन और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग से रिसाइक्लिंग तक पूरी मिनरल वैल्यू चेन छत्तीसगढ़ में विकसित करना है। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ेगा,नए उद्योग स्थापित होंगे और युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स की नीलामी की आठवीं किश्त के रोड शो को संबोधित करते हुए यह बात कही। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स आने वाले समय में देश की आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और सामरिक सुरक्षा के प्रमुख आधार होंगे। आज के तेजी से बदलते वैश्विक और तकनीकी परिदृश्य में इन खनिजों का महत्व बहुत आगे बढ़ चुका है। रक्षा उद्योग से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी,डिजिटल टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग तक आधुनिक अर्थव्यवस्था के लगभग हर उभरते क्षेत्र के लिए इन खनिजों की विश्वसनीय उपलब्धता आवश्यक है। मुख्यमंत्री साय ने ई-रेत संगवारी पोर्टल और टिन पोर्टल का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम द्वारा इंडियन ओवरसीज बैंक तथा पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के साथ महत्वपूर्ण एमओयू भी किए गए। मुख्यमंत्री साय ने उद्योग जगत और निवेशकों से छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा में भागीदार बनने का आह्वान करते हुए कहा कि आज पूरा देश छत्तीसगढ़ की ओर देख रहा है।

विकसित भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स में आत्मनिर्भरता आवश्यक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा...कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से दुनिया की प्रमुख आर्थिक और तकनीकी शक्तियों में अपनी जगह बना रहा है। मेक इन इंडिया,आत्मनिर्भर भारत और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के माध्यम से देश में क्रिटिकल मिनरल्स के अन्वेषण,प्रसंस्करण और इनसे जुड़े उन्नत उद्योगों के विकास को नई गति मिली है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में दुनिया के सभी प्रमुख देश अपने रणनीतिक संसाधनों और उनकी सप्लाई चेन को सुरक्षित करने में जुटे हैं। ऐसे समय में भारत के लिए क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की उपलब्धता में आत्मनिर्भर होना आर्थिक आवश्यकता के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

पूरी मिनरल वैल्यू चेन छत्तीसगढ़ में विकसित करने पर जोर...

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की सोच खनिज उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है। हमारा प्रयास है कि खनिज आधारित उद्योगों की पूरी वैल्यू चेन प्रदेश में विकसित हो। अन्वेषण और उत्खनन के बाद खनिज बाहर भेजने के बजाय उनका प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन और उनसे संबंधित एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश में हो, ताकि प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम आर्थिक लाभ छत्तीसगढ़ और यहां के लोगों को मिले। उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में एआई आधारित डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा राजनांदगांव में इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। ऐसे आधुनिक उद्योगों में क्रिटिकल मिनरल्स की आवश्यकता होगी। खनिज संसाधनों की निकट उपलब्धता प्रदेश को इन उद्योगों के लिए स्वाभाविक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करेगी।

नई औद्योगिक नीति और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से निवेश को प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री साय ने कहा...कि राज्य सरकार नए जमाने के उद्योगों को छत्तीसगढ़ की ओर आकर्षित करने के लिए निवेश अनुकूल वातावरण तैयार कर रही है। नई औद्योगिक नीति में उभरते और भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अधिनियम के माध्यम से कम एवं मध्यम जोखिम वाले उद्योगों के लिए आवश्यक औपचारिकताओं को सरल किया गया है। वन क्लिक सिंगल विंडो सिस्टम 2.0 से विभिन्न अनुमतियों और एनओसी की प्रक्रिया भी सुगम हुई है। उन्होंने कहा कि पूंजी निवेश सहायता,स्टांप शुल्क एवं विद्युत शुल्क में छूट,ब्याज अनुदान और रोजगार आधारित प्रोत्साहन सहित विभिन्न सुविधाएं निवेशकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। राज्य में खनिज संपदा, ऊर्जा,भूमि, कनेक्टिविटी और औद्योगिक अधोसंरचना की उपलब्धता क्रिटिकल मिनरल आधारित उद्योगों के लिए मजबूत इकोसिस्टम तैयार करती है।

खनिज राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि

मुख्यमंत्री ने कहा... कि राज्य निर्माण के समय छत्तीसगढ़ का खनिज राजस्व लगभग 400 करोड़ रुपए था। ढाई वर्ष पहले यह लगभग 12 हजार करोड़ रुपए था,जो अब बढ़कर 16 हजार करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा...कि खनिज संपदा से प्राप्त राजस्व का उपयोग प्रदेश के विकास और जनकल्याण में किया जा रहा है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) के माध्यम से खनन प्रभावित क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ स्थानीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।

रक्षा से एआई तक-नई अर्थव्यवस्था की आधारशिला हैं क्रिटिकल मिनरल्स

मुख्यमंत्री साय ने कहा... कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का रक्षा उद्योग तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय रक्षा क्षमताओं और स्वदेशी तकनीक की प्रभावशीलता को दुनिया ने देखा। आधुनिक रक्षा उपकरणों के निर्माण में अनेक स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग के लिए इनकी सुरक्षित और निरंतर आपूर्ति जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसी प्रकार एआई,सेमीकंडक्टर,बैटरी,क्लीन एनर्जी,इलेक्ट्रिक मोबिलिटी,डिजिटल प्रौद्योगिकी और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिथियम,ग्रेफाइट,रेयर अर्थ एलिमेंट्स,वैनेडियम,निकेल और क्रोमियम जैसे खनिज अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भविष्य की अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका लगातार बढ़ने वाली है।

क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के पास बड़ी संभावनाएं

मुख्यमंत्री साय ने कहा... कि छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख खनिज संपन्न राज्यों में है और अब क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भी प्रदेश नई पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। कटघोरा और बस्तर में लिथियम एवं दुर्लभ मृदा तत्व,बलरामपुर में ग्रेफाइट,वैनेडियम एवं गैलियम,बालोद में फास्फोराइट तथा महासमुंद में निकेल,क्रोमियम और ग्लाकोनाइट की संभावनाएं मौजूद हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा...कि क्रिटिकल एवं स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की नीलामी की आठवीं किश्त में देश के 7 राज्यों के 20 खनिज ब्लॉक्स शामिल हैं, जिनमें छत्तीसगढ़ के 5 ब्लॉक्स हैं। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से इन ब्लॉक्स की नीलामी में सक्रिय भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि यह केवल खनिज ब्लॉक हासिल करने का अवसर नहीं है। यह अन्वेषण,प्रसंस्करण,मूल्य संवर्धन,नवाचार और नए उद्योगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ तथा देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने का अवसर है। ये क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स विकसित भारत के निर्माण की महत्वपूर्ण धुरी बन सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नरसंहार का फैसला टला, अब 5 सितंबर को आएगा निर्णय

जगदलपुर,31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी नरसंहार मामले में सोमवार को फैसला टल गया है। अब जगदलपुर स्थित एनआईए की विशेष अदालत इस मामले में 5 सितंबर को फैसला सुनाएगी।करीब 13 वर्षों से चल रहे इस बहुचर्चित मामले में अदालत की ओर से फैसला सुनाए जाने की तारीख पहले 31 अगस्त निर्धारित की गई थी। झीरम मामले की जांच घटना के दो दिन बाद एनआईए ने अपने हाथ में ली थी। एनआईए ने सितंबर 2014 में आरोप पत्र दाखिल किया। इसके बाद सितंबर 2015 में पूरक आरोपपत्र भी दाखिल किया गया था। इस मामले में शुरुआत में 11 लोगों को आरोपित बनाया गया था। सुनवाई के दौरान ही एक आरोपित की मौत हो चुकी है,जिसके बाद अब शेष 10 आरोपितों पर अदालत अपना फैसला सुनायेगी । मामले की लंबी न्यायिक प्रक्रिया के दौरान 294 सुनवाइयां हुईं। अभियोजन पक्ष ने आरोपितों के खिलाफ दोष साबित करने के लिए अदालत में 101 गवाहों के बयान और महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं। अगस्त 2026 में अभियोजन और बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और 31 अगस्त की तारीख तय की थी। अब फैसला टलने के बाद पीड़ित परिवारों, राजनीतिक दलों और बस्तरवासियों की निगाहें 5 सितंबर पर टिक गई हैं। मामले में जिन आरोपितों के खिलाफ सुनवाई हुई है, उनमें से 10 आरोपित वर्तमान में जगदलपुर केंद्रीय जेल में बंद बताए जा रहे हैं। अब अदालत यह तय करेगी कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप साबित होते हैं या नहीं। झीरम कांड को लेकर वर्षों से यह सवाल भी उठता रहा है कि क्या यह केवल माओवादियों द्वारा किया गया हमला था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। राजनीतिक स्तर पर इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच भी आरोप-प्रत्यारोप होते रहे हैं। हालांकि,अदालत के समक्ष विचाराधीन आरोपों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर ही दोष या निर्दोषता तय होगी। झीरम हमले के बाद नक्सल हिंसा और राजनीतिक नेतृत्व की सुरक्षा को लेकर देशभर में गंभीर सवाल उठे थे।

जांच में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया : भूपेश बघेल

पूर्व मुख्यमंत्री बघेल ने कांकेर में इस मामले पर कहा...कि झीरम घाटी हत्याकांड के पीछे के षड्यंत्रकारियों तक पहुंचने के लिए जांच में कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने तर्क दिया कि जब जांच ही सही तरीके से नहीं हुई है,तो अदालत का फैसला भी केवल उपलब्ध जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही होगा। बघेल ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री के साथ मध्य क्षेत्र की बैठक में झीरम घाटी मामले की जांच राज्य सरकार को सौंपने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि यदि केंद्र सरकार जांच करने में असमर्थ है,तो यह जिम्मेदारी राज्य सरकार को दी जानी चाहिए,लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

बिलासपुर में कोरबा के ट्रांसपोर्टर ने लगाई फांसी

बिलासपुर,31 अगस्त 2026। बिलासपुर में कोरबा के ट्रांसपोर्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी लाश पुरानी बस स्टैंड स्थित शारदा लॉज के कमरे में फंदे पर लटकती मिली। मृतक की पहचान कोरबा के दीपका निवासी प्रतीक जायसवाल (25) के रूप में हुई है। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें उसने लिखा है कि वह पिछले 7-8 महीने से डिप्रेशन में था और काफी तनाव में था। साथ ही मम्मी-पापा से माफी मांगी है। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक दीपका निवासी प्रतीक की दादी बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी देखरेख के लिए वह कोरबा से बिलासपुर आया था। रविवार को उसका छोटा भाई भी बिलासपुर पहुंचा। तीन-चार दिन से अस्पताल में होने के कारण उसने भाई प्रदीप को घर जाने के लिए ऑटो में बैठाया,लेकिन वह घर जाने के बजाए पुराना बस स्टैंड स्थित शारदा लॉज पहुंच गया। वहां कमरा बुक कराने के बाद वह रात में वहीं रुका।

तोखन साहू बन सकते हैं छत्तीसगढ़ बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष.....दिल्ली बुलाए गए

शिवरतन-बृजमोहन की भी चर्चा,7 मोर्चा प्रभारियों की नियुक्ति

रायपुर,31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव सड़क हादसे में घायल हैं। संगठनात्मक गतिविधियों में उनकी सक्रियता सीमित होने के कारण जल्द ही किसी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। इस रेस में केंद्रीय मंत्री और बिलासपुर सांसद तोखन साहू का नाम सबसे आगे चल रहा है। बताया जा रहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तोखन साहू को दिल्ली बुलाया है। इसके अलावा पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा, कुरुद विधायक अजय चंद्राकर,राजनांदगांव सांसद संतोष पांडेय और रायपुर सांसद बृजमोहन अग्रवाल के नाम की भी चर्चा है। इसके अलावा बीजेपी ने प्रदेश के विभिन्न मोर्चों के नए प्रभारियों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की सहमति के बाद 7 मोर्चों के लिए नए प्रभारियों की नियुक्ति की गई है। जारी सूची में युवा मोर्चे से लेकर महिला,किसान,पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक मोर्चे तक जिम्मेदारियां तय की गई हैं। तोखन साहू पिछले करीब एक सप्ताह से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के साथ संगठन और सरकार से जुड़ी महत्वपूर्ण बैठकों में लगातार नजर आ रहे हैं। उनकी बढ़ती सक्रियता को प्रदेश संगठन में नई जिम्मेदारी मिलने की संभावनाओं से जोड़कर देखा जा रहा है। पार्टी के भीतर इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। तोखन साहू वर्तमान में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री हैं और बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भाजपा बस्तर और सरगुजा में मजबूत मानी जाती है, जबकि बिलासपुर संभाग में संगठन को और मजबूत करने की गुंजाइश है। तोखन साहू के अध्यक्ष बनने से पार्टी को इस क्षेत्र में अपना जनाधार बढ़ाने का लाभ मिल सकता है। पार्टी की ओर से औपचारिक घोषणा होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी। छत्तीसगढ़ भाजपा की ओर से जारी सूची के मुताबिक युवा मोर्चे की जिम्मेदारी वैभव बैस को सौंपी गई है। वहीं महिला मोर्चे का प्रभारी सुभाष तिवारी को बनाया गया है। किसान मोर्चे की जिम्मेदारी पूनम चंद्राकर को दी गई है। इसके अलावा पिछड़ा वर्ग मोर्चे का प्रभारी लखनलाल साहू, अनुसूचित जनजाति मोर्चे का प्रभारी शिरिष अग्रवाल और अनुसूचित जाति मोर्चे की जिम्मेदारी डॉ. गुलाब टिकरिहा को सौंपी गई है। वहीं अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी मनोज जैन को नियुक्त किया गया है।

4 सितंबर को कांग्रेस करेगी 'चीनी सत्याग्रह'

शक्कर की बढ़ी कीमतों के खिलाफ छत्तीसगढ़ के हर जिला मुख्यालय में होगा प्रदर्शन

रायपुर,31 अगस्त 2026। चीनी की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस 4 सितंबर को प्रदेशभर में 'चीनी सत्याग्रह' करेगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला मुख्यालयों में एक दिन प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश कांग्रेस की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि देश और प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब, मध्यमवर्गीय और श्रमिक परिवारों पर पड़ रहा है। दैनिक जरूरत की वस्तुओं की कीमत बढ़ने के साथ बाजार में चीनी की उपलब्धता से जुड़ी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटियों को अपने-अपने जिला मुख्यालय में किसी महापुरुष की प्रतिमा के सामने चीनी की बढ़ी कीमतों और कालाबाजारी से राहत की मांग को लेकर सत्याग्रह करने को कहा है। पार्टी ने निर्देश दिए हैं कि कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, अग्रिम संगठन, विभाग, प्रकोष्ठ, निर्वाचित प्रतिनिधि और वरिष्ठ नेताओं समेत सभी स्तर के कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। कांग्रेस का कहना है कि, आम लोगों की जरूरत से जुड़ी वस्तुओं की कीमत और बाजार में उनकी उपलब्धता सीधे तौर पर घरेलू बजट को प्रभावित करती है। इसी मुद्दे को लेकर पार्टी अब चीनी को प्रतीक बनाकर महंगाई के खिलाफ आंदोलन करने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस ने सभी जिला इकाइयों से सत्याग्रह के बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजने के निर्देश भी दिए हैं। यानी 4 सितंबर को प्रदेश के अलग-अलग जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ प्रदर्शन करेंगे।

बिलासपुर हिंसा...सीसीटीवी से उपद्रवियों की पहचान,11 अरेस्ट

2 पक्षों में विवाद के बाद पथराव-तोड़फोड़,टीआई का सिर फटा था,8 पुलिसकर्मी घायल

बिलासपुर,31 अगस्त 2026। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शुक्रवार की रात 2 पक्षों में हुआ विवाद सामुदायिक हिंसा में बदल गया। पथराव और तोड़फोड़ शुरू हो गई। कई गाड़ियों,घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। भीड़ को काबू करने पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस छोड़ी। पथराव में तारबाहर टीआई रवि तिवारी का सिर फट गया। एक आरक्षक समेत कई लोग घायल हुए। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई तेज कर दी है। अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनमें एक पक्ष के 8 और दूसरे पक्ष के 3 आरोपी शामिल हैं। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और दूसरे डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर हिंसा में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर रही है।

कथित हिंदू विरोधी टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद

पुलिस के मुताबिक खपरगंज के पास स्थित बिरयानी सेंटर के पास युवकों के बीच छींटाकशी और कथित हिंदू विरोधी धार्मिक टिप्पणी को लेकर विवाद शुरू हुआ था। बहस बढ़ी तो दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। पुलिस के पहुंचने से पहले एक बुजुर्ग के घायल होने की जानकारी सामने आई। इसके बाद दोनों पक्षों के लोग मौके पर पहुंचने लगे और विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। खपरगंज से शुरू हुआ पथराव और तोड़फोड़ आसपास के इलाकों तक पहुंच गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को काबू में किया।

हिंसा के बाद शहर में बढ़ाई गई सुरक्षा

इस घटना के बाद संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाई गई और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी गई। अधिकारियों ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के कोई पोस्ट या वीडियो शेयर नहीं करने की अपील की।

11 गिरफ्तार,दोनों पक्षों पर कार्रवाई

SSP रजनेश सिंह के मुताबिक ठाकुर रामसिंह और सोहेल खान समेत अन्य संदिग्धों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ केवल नाम सामने आने के आधार पर कार्रवाई नहीं होगी। सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और पूछताछ से मिले तथ्यों का सत्यापन किया जा रहा है।

राहुल गांधी के समर्थन में सड़क पर उतरी कांग्रेस एफआईआर को बताया राजनीतिक प्रतिशोध

रायपुर,31 अगस्त 2026। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ उत्तराखंड में दर्ज एफआईआर के विरोध में रायपुर में कांग्रेस ने पैदल मार्च निकाला। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर रायपुर ग्रामीण और शहर जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अंबेडकर चौक से सिविल लाइन थाना तक पैदल मार्च किया। मार्च का नेतृत्व रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे और रायपुर शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष कुमार शंकर मेनन ने किया। कांग्रेस ने उत्तराखंड के हल्द्वानी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ भाजपा-आरएसएस कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए कथित जातिवादी शुद्धिकरण अनुष्ठान का भी विरोध किया। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में शामिल भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की। पैदल मार्च के बाद कांग्रेस नेताओं ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की।

रायपुर ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र पप्पू बंजारे और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने संयुक्त रूप से कहा कि जातिगत भेदभाव का विरोध करना अपराध नहीं है। राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय,संविधान और समानता के पक्ष में आवाज उठाई है। दोषियों पर कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)